



कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध

वर्ष-10, अंक-12, मार्च 2018, ईमेल: krishichaupal@gmail.com, वेबसाइट: krishichaupal.com

रुपये 20



महाराष्ट्र में दिखाया
किसानों ने दम

पीएनबी
क्रेडिट कार्ड

**आकर्षक उपहारों के साथ
पीएनबी क्रेडिट कार्ड**



बैंकिंग सेवाओं और उत्पादों की जानकारी के लिए, डायल करें 1800 180 2222, 1800 103 2222 (टोल फ्री) या डायल करें 0120-2490000 (टोलड)
अथवा 5607040 पर PNB PROD एसएमएस करें [@indiapnb](https://twitter.com/indiapnb) [f](https://www.facebook.com/indiapnb) [in](https://www.linkedin.com/company/indiapnb) www.pnbindia.in

पंजाब नैशनल बैंक **PNB** **punjab national bank**
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

उत्तराखण्ड के द्वार हरिद्वार में प्लॉट

हरी कुंज-फेस-1 में मात्र ₹ 2.50 लाख (100 Sq. Yard)

फेरुपुर, लक्सर रोड़, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

रानीपोखरी,
देहरादून
में रु. 6000/-
प्रति गज

पीरभदर,
रामनगर
में रु. 3750/-
प्रति गज

LOAN FACILITY AVAILABLE

FREE SITE VISIT FACILITY

DEV BHOOMI
EVELOPERS

BUILDING TOMORROW

Devbhoomi Developers

Delhi Off.: "NAVAKAR BUILDING" 138 B/ 2, 11nd Floor, Mohammadpur, Near Bhikaji Cama Place, New Delhi-66

Dehradun Off.: Near Jolly Grand Airport, Dehradun-Rishikesh N.H., Dehradun Uttarakhand

9891955999, 8285222202, 9990057314, 011-26715123

website : www.devbhoomidevelopers.com Email: uk@devbhoomidevelopers.com



कृषि चौपाल

कृषि एवं आमोषन सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध

वर्ष-10 ❖ अंक-12 ❖ मार्च 2018

संपादक
महेन्द्र सिंह बोरा

संपादक मंडल
डॉ. गंगाशरण सैनी, एस. विश्वजीत,
गणेश पांडे, ताज रावत, महेश पपने

राजनीतिक संपादक
ललित पांडे

पंजाब-हरियाणा-चंडीगढ़ प्रभावी
अभिषेक चन्द्रा

प्रसार प्रबंधक
दलीप जीना

डिजाइन
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स

संपादकीय कार्यालय

कृषि चौपाल

सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9,
वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092

संपर्क: +91-9910406059

ईमेल: krishichoupal@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक
महेन्द्र सिंह बोरा द्वारा सी-355, तृतीय तल,
गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092
से प्रकाशित और श्री इंटरप्राइजेज, डी-93,
सैक्टर-7, नौएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश से मुद्रित।

'कृषि चौपाल' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये
विचार लेखकों की अपनी अभिव्यक्तियाँ हैं। संपादकीय
मंडल का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। 'कृषि
चौपाल' में दिये गये विभिन्न उपचारों, सुझावों पर
अमल करने पर यदि किसी को किसी प्रकार की क्षति
होती है तो इसके लिए 'कृषि चौपाल' को जिम्मेदार
नहीं ठहराया जा सकता है। सुझाये गये विभिन्न उपचारों
और परामर्शों पर अमल करने से पूर्व संबंधित विशेषज्ञों
की राय को प्राथमिकता दें। किसी भी तरह के विवाद
का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाले
सक्षम न्यायालयों और फोरमों में ही किया जाएगा।

चित्र साभार: google.com

● उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं।

खेती एक ऐसा जुआ है जिसमें हारता सिर्फ किसान है

पिछले चार साल किसानों के लिए आफत के रहे। पहले दो सालों में भयंकर सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी। तीसरे साल जब अच्छी आस जगी और भरपूर अनाज, दलहन, प्याज, टमाटर, आलू, कपास का उत्पादन हुआ तो इनकी कीमतें जमीन पर आ गईं। क्योंकि राज्य सरकारों के पास उसके विपणन और भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में किसानों ने गुस्से में अपनी उपज सड़कों पर फेंकनी शुरू कर दी। एक मजबूर किसान इसके सिवा कर भी क्या सकता था। अब चौथे साल, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2017-18 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों (जो अभी 27 फरवरी को जारी किये गये हैं) के अनुसार खाद्यान्न खासकर चावल, मोटे अनाज और दलहन में फिर रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। ऐसे में जब खूब पैदावार होगी तो फिर वही हाल होगा और किसानों को मजबूरी में अपनी उपज औने-पौने दामों में बेचनी पड़ेगी। मतलब जब उपज कम हो तो मुसीबत और जब खूब बरसे तो मुसीबत ही मुसीबत। ऊपर से उसे 'अन्नदाता' कहकर और चिढ़ा दिया जाता है। इतना लाचार, बेवश और फटेहाल प्राणी अन्नदाता कैसे हो सकता है।

इस पूरे खेल में एक वर्ग ऐसा है जो हमेशा मौज में रहता है, वह है व्यापारी। जब उत्पादन ज्यादा हो तो कीमत कम करके व्यापारी मालामाल हो जाता है। और जब उत्पादन कम हो तो कीमतें ऊंची कर व्यापारी फिर मालामाल हो जाता है। यानी किसान बचे या मरे उसके धंधे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दोनों स्थितियों में मजे में है। इस जुए के खेल में हर बार किसान को ही हारना पड़ता है।

कितने आश्चर्य और दुख की बात है कि आजादी के 70 साल बाद भी राज्य सरकारें किसान की हाड़तोड़ मेहनत के बाद उपजाई गयी उपज को सहेजने की स्थिति में तक नहीं हैं। आये दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी औलादें खेतीबाड़ी छोड़ फैंक्ट्री में मजदूरी करना अच्छा समझ रही हैं। इससे सरकारों की किसानों के कल्याण की चिंता साफ दिखती है। उधर दूसरी तरफ केंद्र सरकार को इतनी विशाल आबादी के पेट भरने की चिंता रही है और वह रूस, इंडोनेशिया, म्यांमार आदि देशों में खाली पड़ी जमीन पर खेती करने की सोच रही है। कितनी दुखद स्थिति है कि अपनी खेतीबाड़ी चौपट कर हम दूसरे के खेत आबाद करने जा रहे हैं।

ऑक्सफेम की रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो कृषिक्षेत्र की स्याह दुनिया साफ नजर आती है। देश में वर्ष 2017 में जो कुल पूंजी पैदा हुई उसमें ऊपर के एक प्रतिशत लोगों के पास देश की 73 प्रतिशत पूंजी चल गयी जबकि 99 प्रतिशत लोगों के पास मात्र 27 प्रतिशत पूंजी आयी। इस 27 प्रतिशत में शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग जो नौकरीपेशा या छुटपुट काम-धंधा करता है उसका बड़ा हिस्सा निकाल दें तो किसान के पास हाथ आया ही क्या?

देश के अरबपतियों में 37 प्रतिशत तो ऐसे हैं जिन्हें बिना कुछ किये कराये यह संपत्ति विरासत में मिली है। इन बड़े लोगों के पास देश की कुल 20.90 लाख करोड़ की संपत्ति है जो लगभग भारत के सालाना बजट के बराबर है। 2000 में यह देश की कुल पूंजी का 37 प्रतिशत थी जो 2005 में बढ़कर 42 प्रतिशत, 2010 में 48 प्रतिशत, 2012 में 52 प्रतिशत और आज 58 प्रतिशत हो गयी है। क्या यही होता है समावेशी विकास? निश्चित तौर पर इस देश के अंदर दो देश बन गये हैं- एक बेहद अमीर और दूसरा बेहद गरीब।

अभी मोदी सरकार ने इस साल के बजट में किसानों की सुध ली है। क्योंकि यह पांच साला सरकार का आखिरी बजट है और किसानों को अपने भाग्यविधाताओं को फिर संसद भेजना है। ऐसी पहल सरकार बनते ही शुरू कर दी होती तो शायद हालात बहुत सुधर गये होते। लेकिन उम्मीद तो की ही जा सकती है। उम्मीद में तो किसानों की पीढ़ियां गुजर गयीं। इसके सिवा चारा भी क्या है।

म.सि.बोरा

(महेन्द्र सिंह बोरा)

भारत और ईरान के बीच कृषि सहयोग को मंजूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ईरान के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए पूर्वव्यापी समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 17 फरवरी, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

समझौता ज्ञापन में कृषि फसलों, कृषि विस्तार, बागवानी, मशीनरी, फसल के बाद प्रौद्योगिकी, पादप संगरोध उपाय, ऋण एवं सहकारिता के क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है। इसमें मृदा संरक्षण और जल प्रबंधन, समेकित पोषक प्रबंधन, बीज प्रौद्योगिकी, कृषि विपणन की भी व्यवस्था है। इस समझौते के दायरे में आने वाले आपसी सहमति से निर्धारित अन्य क्षेत्रों में पशुधन सुधार, डेयरी विकास, पशु स्वास्थ्य भी

शामिल हैं। यह सहयोग विशेषज्ञों, सामग्री और सूचना के आदान-प्रदान, अध्ययन, दौरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रशिक्षुओं और वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान, उपयुक्त सम्मेलनों और कार्यशालाओं की सुविधा तथा परस्पर रूप से सहमत अन्य उपायों के जरिए किया जाएगा। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत इसे पूरा करने में होने वाले कार्यकलापों की निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्यदल गठित किया जाएगा। इस दल की बैठक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार बारी-बारी से ईरान और भारत में होगी। समझौता ज्ञापन पहले पांच वर्षों के लिए मान्य होगा और उसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए स्वतः ही इसका विस्तार हो जाएगा, जब तक कि कोई भी एक पक्ष इसे समाप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट न कर दे।

रबी विपणन मौसम 2018-19 के दौरान 320 लाख टन गेहूं की खरीद का अनुमान

सरकार ने रबी विपणन मौसम 2018-19 के लिए 320 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह फैसला सचिव (खाद्य) श्री रविकांत की अध्यक्षता में राज्यों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में किया गया। सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के लिए भी 55 लाख टन धान/चावल की खरीद का लक्ष्य रखा है।

राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे खरीद केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी करें और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में विस्तार से प्रचार करें और सुनिश्चित करें कि किसानों को जल्द उनकी उपज का भुगतान मिल जाए।

2018-19 के दौरान गेहूं खरीद अनुमान का राज्यवार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य	गेहूं खरीद अनुमान (लाख मीट्रिक टन)
1.	पंजाब	119.00
2.	हरियाणा	74.00
3.	मध्य प्रदेश	67.00
4.	उत्तर प्रदेश	40.00
5.	राजस्थान	16.00
6.	बिहार	2.00
7.	उत्तराखंड	1.00
8.	गुजरात	0.50
9.	अन्य राज्य	0.50
	योग	320.00

2018-19 के दौरान धान/चावल खरीद अनुमान का राज्यवार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य	धान खरीद अनुमान (लाख मीट्रिक टन)
1.	आंध्र प्रदेश	18.00
2.	तेलंगाना	19.00
3.	ओडिशा	7.00
4.	तमिलनाडु	5.00
5.	केरल	1.32
6.	पश्चिम बंगाल	4.00
7.	असम	0.34
8.	महाराष्ट्र	0.34
	योग	55.00

पूर्वोत्तर में खट्टे फलों के प्रसंस्करण का काम करेगा इजराइल

इजराइल के सहयोग से पूर्वोत्तर में पहले क्षेत्रीय कृषि केन्द्र का उद्घाटन मिजोरम में किया गया। लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित यह केन्द्र विशेष रूप से खट्टे फलों के प्रसंस्करण के लिए होगा। यह परियोजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, मिजोरम राज्य सरकार और इजराइली सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। इजराइल विशेषज्ञता और व्यावसायिक समर्थन प्रदान करेगा। मिजोरम में स्थित यह केन्द्र पूरे पूर्वोत्तर की आवश्यकताएं पूरी करेगा। भारत में इस तरह के 22 परिचालन केन्द्र मौजूद हैं, जिनमें हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब शामिल हैं। पहला केन्द्र 2008 में हरियाणा में स्थापित किया गया था। उद्घाटन के अवसर पर इजराइल के राजदूत ने कहा कि इजराइल प्रत्येक राज्य में ऐसे केन्द्र खोलना चाहता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र



प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इस केन्द्र से दोनों देशों के बीच बड़े सहयोग का सूत्रपात हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय आवश्यकता अनुसार पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि आगे चलकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को इससे बहुत फायदा होगा और अन्य क्षेत्रों के किसानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सिक्किम को भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया है और इजराइल इस दिशा में सहयोग कर सकता है।

मिर्च की खेती से करोड़पति बना किसान



ऐसा नहीं है कि खेती में लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। कमाने वाले कमा भी रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा, कोई ज्यादा, तो कोई अच्छा खासा। इन्हीं में से एक हैं जगन्नाथ राय और उनका परिवार। बस्तर जिले के मालगांव से ताल्लुक रखने वाले राय पांच भाइयों के साथ हरी मिर्च की खेती करते हैं। पिछले सीजन में तो पांचों भाइयों की टीम ने पचास एकड़ खेत में मिर्च की खेती से रिकार्ड पैदावार हासिल की। अब तक एक हजार टन से अधिक की मिर्च सात महीने की फसल से ही पैदा की। जिसे बाजार में बेचकर उन्होंने एक करोड़ से अधिक का लाभ कमाया। ताज्जुब की बात यह है कि वह सिर्फ सातवीं क्लास तक ही पढ़े हैं।

राय के पास खुद की बीस एकड़ जमीन है। इसके अलावा और 30 एकड़ खेत लीज पर ले रखा है जिसका किराया 15 से 20 हजार रुपए प्रति एकड़ सालाना है।

जगन्नाथ राय के पास अब ट्रैक्टर, रोटर, थ्रेशर, केजविल और कल्टीवेटर जैसी खेती की आधुनिक मशीनें हैं। इसके अलावा वे खेती के लिए मल्लिचंग तकनीक इस्तेमाल करते हैं ताकि बेहतर उत्पादन लेने के साथ साथ नुकसान से भी बचा जा सका।

करीब 15 साल पहले जगन्नाथ ने मिर्च की खेती शुरू की थी। उन्होंने पहले 7 एकड़ में मिर्च की फसल लगाई। जब उम्मीद से अधिक फायदा होने लगा तो वे साल दर साल खेती का रकबा बढ़ाते गए। अब राय 7 एकड़ से बढ़ाकर करीब 50 एकड़ में खेती करते हैं। जगन्नाथ अपने आप में खेती-किसानी के बेहतरीन उदाहरण हैं कि केवल मिर्च की खेती से भी करोड़पति बना जा सकता है।



सोलर पंप लगाने के लिए सरकार देगी 60 प्रतिशत सब्सिडी

आम बजट 2018-19 से केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर आधारित बनाया जाएगा। योजना के तहत 2022 तक देश में तीन करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। कुसुम योजना पर कुल 1.40 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें केन्द्र सरकार 48 हजार करोड़ रुपये योगदान करेगी जबकि इतनी ही राशि राज्य सरकारें देंगी।

किसानों को सौर ऊर्जा यंत्र को लगाने के लिए सिर्फ 10% राशि का अग्रिम भुगतान करना होगा, जबकि बैंक किसानों को बैंक ऋण के रूप में कुल व्यय का 30% हिस्सा प्रदान करेगा। बाकी का 60% हिस्सा सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप देगी। मान लीजिए यंत्र एक लाख का लगता है तो किसान 10,000 रुपए देगा, बैंक ऋण के

रूप में 30,000 रुपए देगा और सरकार 60,000 रुपए सब्सिडी के रूप में देगी।

योजना के तहत पहले चरण उन पंपों को शामिल किया जाएगा जो डीजल से चल रहे हैं। इस तरह के 17.5 लाख सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने की व्यवस्था की जाएगी। यह योजना किसानों को दोहरा फायदा पहुंचाएगी। एक तरफ उन्हें मुफ्त में सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी और दूसरी तरफ वे अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर उसके बदले पैसा भी कमा सकते हैं।

माना जा रहा है कि यदि देश के सभी सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने में कामयाबी हासिल कर ली जाए तो न केवल मौजूदा बिजली की बचत होगी बल्कि करीब 28 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी संभव हो सकेगा।

योजना का विस्तृत प्रस्ताव सचिवों की समिति को भेजा गया है उसके बाद कैबिनेट इसे मंजूरी देगा। योजना को आगामी वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा।

अप्रैल तक काम करने लगेगा आईपीपीबी

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का अप्रैल 2018 तक काम करने की उम्मीद है। इसके बाद आईपीपीबी देश में सबसे बड़ा वित्तीय समावेश नेटवर्क उपलब्ध कराने में समर्थ होगा जिसमें शहरी और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे और जिसमें डाकियों

एवं ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की मदद से लोगों के दरवाजों तक डिजिटल भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता होगी। आईपीपीबी डाकघर 17 करोड़ खाताधारकों को एनईएफटी, आरटीजीएस, बिल भुगतान जैसी सेवाओं का लाभ देगा।

With Best Compliments From



G. S. RAWAT

B.Sc. Engg. DCE, MIE
Chairman & Managing Director

HYTHRO ENGINEERS PVT. LTD

हाइथ्रो इंजीनियर्स प्रा. लि.

SUPREME ADVERTISING PVT. LTD.

सुप्रीम एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.

HANCRAFT EXPO DESIGNS PVT. LTD.

हेंनक्राफ्ट एक्सपो डिजाइंस प्रा. लि.

302-303, Bhikaji Cama Bhawan
11, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Phone: 011-26186038, 26180238

hythroengineers@airtelmail.in | supremeadvertising@airtelmail.in



उज्ज्वला योजना के लक्ष्य में बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। पीएमयूवाई को महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की ओर से व्यापक समर्थन मिलने और अब तक एलपीजी कनेक्शन से वंचित घरों को इसके दायरे में लाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है। उम्मीद की जा

रही है कि पीएमयूवाई का संशोधित लक्ष्य वर्ष 2020 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। सरकार देश भर में उन सभी परिवारों को एलपीजी के जरिये स्वच्छ रसोई ईंधन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है जो अब तक इसके दायरे में नहीं आ पाये हैं। पीएमयूवाई की शुरुआत मई 2016 में हुई थी जिसके जरिये लाभार्थियों को नकद सहायता दी जाती है, ताकि वे बगैर किसी

जमानत राशि (डिपॉजिट) के नया कनेक्शन प्राप्त कर सकें। पीएमयूवाई के तहत आरम्भ में वित्त वर्ष 2016-17 से शुरू 3 वर्षों की अवधि के दौरान 8,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 5 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। यह सभी तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने संबंधी सरकार के समग्र फोकस का एक हिस्सा है।

नेफेड द्वारा दालों और तिलहनों की खरीद के लिए सरकारी गारंटी बढ़ी

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा न्यूनतम समर्थन योजना के अंतर्गत दालों और तिलहनों की खरीद के लिए तथा छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम को उसकी वर्तमान देनदारी पूरी करने और मौजूदा दावों को निपटाने के लिए 45 करोड़ रुपए देने के लिए ऋण देने वाले बैंक को सरकारी गारंटी की सीमा सीमा 9,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19,000 करोड़ करने के सरकारी गारंटी के नियमन और विस्तार को मंजूरी दे दी गयी है। यह सरकारी गारंटी भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए यानी 2021-22 तक दी गई है और इसमें एक प्रतिशत का सरकारी गारंटी शुल्क माफ किया गया है।

इससे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य से दालों और तिलहनों के बाजार मूल्य कम होने के कारण सरकारी गारंटी प्रावधान से दाल और तिलहान उपजाने वाले किसानों को तेज आवक अवधि के दौरान मजबूरन बिक्री करने से रोकने में मदद मिलेगी।

खेती-किसानी से संबंधित बजट 2018-19 के मुख्य बिन्दु

बजट 2018 मुख्यतया कृषि एवं किसान कल्याण विषयों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता तथा प्रधानमंत्री के 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को परिलक्षित करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजटीय आवंटन वर्ष 2017-18 में 51,576 करोड़ था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 58,080 करोड़ कर दिया गया है। प्रक्षेत्रवार 5 वर्ष के बजटीय प्रावधानों की स्थिति इस प्रकार है-

प्रक्षेत्र	बजटीय प्रावधान (करोड़ में)		वृद्धि
	2009-14	2014-19	
फसल बीमा	6,182	33,162	436%
माइक्रो इरिगेशन	3193	12711	298%
सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट	162	1,573	871%
कृषि यंत्राकरण	254	2408	846%
कृषि विस्तार उपमिशन	3163	4046	28%
कृषि विपणन	2666	6150	131%
वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास	189	1322	700%
डेयरी विकास	8114	10725	32%
नीली क्रांति	1772	2913	64%
कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार	12252	13748	12%

बजटीय आवंटन के अलावा:

- सूक्ष्म सिंचाई कोष 5,000 करोड़
- डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना कोष 10,881 करोड़ का कार्पस फंड
- कृषि बाजार संसाधन फंड 2,000 करोड़
- मात्स्यिकी, कृषि संसाधन विकास एवं पशुपालन संसाधन विकास फंड 10,000 करोड़



संकर बीजों का बीजगणित

देसी बीजों की यह विशेषता है कि बार-बार उपयोग के बाद भी इनकी उत्पादन क्षमता कम नहीं होती है, मगर आज हमारे सामने अनाज, सब्जियों और अन्य प्रकार के जो संकर बीज हैं उनमें यह क्षमता नहीं है। एक-दो बार उपयोग के बाद इनमें इतनी क्षमता नहीं रहती कि इन्हें बोकर लाभ कमाया जा सके।

■ डॉ. महर उद्दीन खां

भारत में अधिक उत्पादन देने वाले बीजों को कृषिक्षेत्र में क्रांति माना जाता है। ऊपर से देखने में यही आभास होता है कि अधिक उत्पादन देने वाले संकर बीज देकर मल्टीनेशनल कंपनियों ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मगर यह बात इतनी सरल नहीं है। जब बीजों के इस गणित पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि हमने नये संकर बीज अपनाकर इन मल्टीनेशनल कंपनियों पर बड़ा उपकार किया है जिसके लिए इन कंपनियों को भारत का सदैव आभारी होना चाहिए। दरअसल इन बीजों का गणित केवल अधिक उत्पादन तक ही सीमित नहीं है बल्कि बीजों के अनवरत उत्पादन का भी गणित है।

देसी बीजों की यह विशेषता है कि बार-बार उपयोग के बाद भी इनकी उत्पादन क्षमता कम नहीं होती है, मगर आज हमारे सामने अनाज, सब्जियों और अन्य प्रकार के जो संकर बीज हैं उनमें यह क्षमता नहीं है। एक-दो बार उपयोग के बाद इनमें

इतनी क्षमता नहीं रहती कि इन्हें बोकर लाभ कमाया जा सके। हर दो साल बाद किसान को नये बीज की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बीज उत्पादक कंपनियों का धंधा अबाध गति से चलता रहता है।

इन संकर बीजों की एक कमजोरी यह है कि केवल गोबर या कूड़े-करकट की खाद से इनसे उत्पादन नहीं लिया जा सकता। इनसे भरपूर उत्पादन लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अनिवार्य होता है। गन्ना, गेहूँ, चावल और अन्य फसलों के प्रचलित नये बीजों से अधिक उत्पादन लेने के लिए डीएपी और यूरिया का प्रयोग अनिवार्य है। इस प्रकार इन उर्वरकों से बचाव के लिए किसान के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। डीएपी जैसे महंगे उर्वरक के उत्पादन पर भी इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों का एकाधिकार है। इस प्रकार बीज के साथ-साथ इन कंपियों का उर्वरक उत्पादन का धंधा भी अनवरत जारी रहता है।

देसी बीजों में रोगों तथा खर-पतवार का मुकाबला करने की क्षमता होती थी, मगर नये बीजों में यह क्षमता नहीं है। इनसे उत्पादन लेने

के लिए कीटनाशक एवं खर-पतवार नाशक दवाइयों का उपयोग करना भी मजबूरी बन गया है। जो किसान अबसे चार-पांच दशक पहले जहरीली दवाइयों के प्रयोग को अपराध मानता था वह आज धड़ल्ले से इनका प्रयोग कर रहा है, क्योंकि बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। इस प्रकार एक बीज के साथ-साथ उर्वरक, खर-पतवार नाशक और कीटनाशकों की खेप भी साथ में आ गयी।

नये बीजों के बीजगणित की इस श्रृंखला का समापन यहीं नहीं हो जाता। इससे आगे भी और कई धंधों का विकास इन नये बीजों ने किया है। देसी बीज भारतीय जलवायु के अनुकूल होते थे, इसलिए मौसम के अनुसार इनके सेवन से रोगों की संभावना कम रहती थी। नये बीजों के आगमन से पहले गेहूँ मुख्य भोजन में शामिल नहीं था। लोग मौसम के अनुसार मोटे अनाज का प्रयोग करते थे मगर अब ऐसा नहीं है। गेहूँ हमारा मुख्य भोजन बन गया है। मिस्सी रोटी घरों से गायब हो गई है और आज की पीढ़ी को बेझड़ के बारे में पता ही नहीं है। जिसका नतीजा है कि आज हर आदमी कब्ज, गैस, एसिडिटी और मोटापा आदि किसी न किसी रोग का शिकार है। नये बीजों के आगमन से पहले ये रोग आम नहीं थे। लोक मान्यता है कि मोटा अनाज खाने वाले लोग मोटे नहीं होते। इन रोगों से बचाव के लिए अनेक दवाइयाँ भी आ गई हैं। इन दवाइयों का उत्पादन भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ ही करती हैं। इस प्रकार एक बीज ने दवा उद्योग को भी खूब लाभ पहुंचाया है।

नये बीजों ने जहां एक ओर मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए समृद्धि के द्वार खोले हैं वहीं भारत के सामने कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर दी हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल न तो भारत के पास है और न ही इन मल्टीनेशनल कंपनियों के पास। देसी बीजों के लिए पानी की आवश्यकता कम होती थी जबकि नए बीजों के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। गेहूँ का कोई भी नया बीज चार-पांच सिंचाई से कम पर समुचित उत्पादन नहीं दे सकता, जिसका नतीजा यह है कि भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कई इलाकों में तो नलकूप तीन-चार साल बाद ही बेकार हो जाते हैं। भूजल का लगातार गिरता स्तर किसान और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है, मगर अभी तक इसका कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। ●



उपलब्धि

इस साल देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन

सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2017-18 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों को 27 फरवरी 2018 को जारी किया गया है। विभिन्न फसलों के उत्पादन का मूल्यांकन राज्यों से प्राप्त प्रतिपुष्टियों तथा इसकी वैधता अन्य स्रोतों से उपलब्ध सूचना पर आधारित है। दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2017-18 के दौरान मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है-
 खाद्यान्न - 49 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
 चावल - 111.01 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
 गेहूं - 97.11 मिलियन टन
 मोटे अनाज - 45.42 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
 मक्का - 27.14 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
 दलहन - 23.95 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
 चना - 11.10 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
 तूर- 4.02 मिलियन टन
 उड़द - 3.23 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
 तिलहन - 29.88 मिलियन टन
 सोयाबीन- 11.39 मिलियन टन
 मूंगफली- 8.22 मिलियन टन
 अरंडी बीज - 1.50 मिलियन टन
 कपास - 33.92 मिलियन गांठें (प्रति 170 किलोग्राम की)
 गन्ना - 23 मिलियन टन

मानसून 2017 के दौरान लगभग सामान्य वर्षा एवं सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप मौजूदा वर्ष में देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। 2017-18 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों

के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 277.49 मिलियन टन तक अनुमानित है जो 2016-17 के दौरान विगत 275.11 मिलियन टन के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 2.37 मिलियन टन अधिक है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन भी विगत पांच वर्षों (2012-13 से 2016-17) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 17.31 मिलियन टन अधिक है।

2017-18 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 111.01 मिलियन टन अनुमानित है। चावल का उत्पादन 2016-17 के दौरान प्राप्त विगत 109.70 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 1.31 मिलियन टन अधिक है। यह पांच वर्षों के 106.29 मिलियन टन के औसत उत्पादन की तुलना में भी 4.71 मिलियन टन अधिक है।

गेहूं का उत्पादन 97.11 मिलियन टन अनुमानित है जो 2016-17 के दौरान प्राप्त विगत 98.51 मिलियन टन के रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन की तुलना में 1.40 मिलियन टन कम है। तथापि, 2017-18 के दौरान गेहूं का उत्पादन इसके औसत गेहूं उत्पादन की तुलना में 3.77 मिलियन टन अधिक है।

मोटे अनाजों का उत्पादन 45.42 मिलियन टन अनुमानित है जो औसत उत्पादन की तुलना में 3.72 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, यह 2016-17 के दौरान प्राप्त 43.77 मिलियन टन के विगत उत्पादन की तुलना में 1.65 मिलियन टन अधिक है।

2017-18 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 23.95 मिलियन टन तक

अनुमानित है जो विगत वर्ष के दौरान प्राप्त 23.13 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 0.82 मिलियन टन अधिक है। इसके अतिरिक्त, 2017-18 के दौरान दलहनों का उत्पादन पांच वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 5.10 मिलियन टन अधिक है।

2017-18 के दौरान तिलहनों का कुल उत्पादन 29.88 मिलियन टन अनुमानित है जो 2016-17 के दौरान प्राप्त 31.28 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 1.39 मिलियन टन कम है। तथापि, 2017-18 के दौरान तिलहनों का उत्पादन इनके औसत उत्पादन की तुलना में मामूली रूप से 0.34 मिलियन टन अधिक है।

2017-18 के दौरान गन्ने का उत्पादन 353.23 मिलियन टन अनुमानित है जो 2016-17 की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से 47.16 मिलियन टन अधिक है। गन्ना उत्पादन पांच वर्षों के 342.04 मिलियन टन के औसत उत्पादन की तुलना में भी 11.19 मिलियन टन अधिक है।

कपास का उत्पादन 33.92 मिलियन गांठें (प्रति 170 किलोग्राम की) अनुमानित है जो विगत वर्ष के 32.58 मिलियन गांठों के उत्पादन की तुलना में अधिक है। इसके अलावा, यह पांच वर्षों के 33.50 मिलियन गांठों के औसत उत्पादन की तुलना में भी 0.41 मिलियन गांठें अधिक है।

पटसन एवं मेस्टा का उत्पादन 10.51 मिलियन गांठ (प्रति 180 किलोग्राम की) अनुमानित है जो 2016-17 के दौरान प्राप्त उत्पादन की तुलना में कम है। ●

भारत के 29 राज्यों की सड़क यात्रा मात्र 39 दिनों में पूरा करेंगी शिवांगी



चंडीगढ़ की रहने वाली शिवांगी शर्मा, जो कि पेशे से एक वकील हैं, उन्होंने महिला दिवस पर एक प्रेस वार्ता में यह घोषणा की कि वे अकेले पूरे भारत के भ्रमण पर निकलने वाली हैं और अपनी इस सड़क यात्रा के दौरान वे 39 दिनों में देश के 29 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी (केंद्र शासित प्रदेश) से होकर गुजरेंगी। शिवांगी पहले दिन श्रीनगर से अपनी कार में यह यात्रा शुरू करेंगी और प्रत्येक दिन औसतन 450 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। वह इस यात्रा के दौरान 100 से अधिक शहरों से गुजरेंगी और 39 दिनों में देश के सभी 29 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेंगी। शिवांगी की यह यात्रा लगभग 17000 किलोमीटर की कुल दूरी को तय करेगी।

अपनी योजना पर बोलते हुए, शिवांगी शर्मा ने कहा, “हमारा देश कमाल का सुन्दर है और मैं बचपन से ही इसकी खूबसूरती को देखना चाहती हूँ। अपने देश के हर कोने की यात्रा करने का मेरा सपना था और अब मेरे दोस्तों और परिवार की मदद से, मैं अपने सपने को पूरा करने वाली हूँ। मैं भारत की पहली महिला होऊंगी, जो अकेले 29 भारतीय राज्यों को 39 दिनों में कवर करके यह साबित करेगी कि एक महिला कुछ भी कर सकती है।”



शिवांगी शर्मा के इस सपने को हासिल करने में कई युवा मदद कर रहे हैं जिनमें प्रमुख है हंगरी ट्रिपर के सिद्धार्थ बेकाय जिन्होंने इस यात्रा की पूरी रूपरेखा तैयार की है और गौरव चौहान जो इस यात्रा को कैमरे में कैद करेंगे। इस यात्रा में कई सृजनात्मक तत्व शामिल हैं, जो हमारे देश की अविश्वसनीय खूबसूरती को एक एकल महिला यात्री की आंखों से लोगों को दिखायेगी। भारत की अग्रणी पीआर एजेंसियों में से एक, क्रिएटिविज्ट कम्युनिकेशंस के ऋषु मोंगा द्वारा यात्रा को प्रमोट किया जा रहा है, जो शिवांगी की कहानी को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे।

शिवांगी जी ने अंत में कहा कि ‘मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि यदि एक महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मेरी यह यात्रा महिला सशक्तिकरण के बारे में है। मैं उस हर एक व्यक्ति के प्रति बहुत आभारी हूँ जो मुझे अपना सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि मेरी यात्रा से पूरे भारत को यह संदेश मिलेगा कि हमारा देश एक महिला यात्री के लिए सुरक्षित है।’

For more information, please contact:

Arjun Goel (+91-9873483718)

Rishu Monga (+91-9971722917)

Creativizt Communications | <http://creativizt.com>



ग्रामीण भारत से वायदा निभाने का वक्त

■ एन के सिंह

सरकार ने अपने आखिरी पूर्ण बजट में शहरी मध्यम एवं उच्च वर्ग की अपेक्षाओं को लगभग नजरअंदाज करते हुए ग्रामीण भारत पर अपना दांव लगाया है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात चुनाव के बाद यह अहसास हुआ कि किसानों को नाराज कर वह आगामी आम चुनाव की वैतरणी पार नहीं कर पाएंगे। इसकी एक झलक राजस्थान में दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों से भी मिली। भाजपा की ये तीनों सीटें कांग्रेस ने छीन लीं। अगर उपचुनाव परिणाम बजट के दिन नहीं आए होते तो शायद देश उन्हीं पर चर्चा कर रहा होता। जो भी हो, आम बजट पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। शहरी माध्यम एवं उच्च वर्ग जहां निराशा जता रहा है वहीं ग्रामीण भारत को एक आस नजर

आ रही है। बजट के गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उसमें जो घोषणाएं की गई हैं वे ग्रामीण भारत के लिए पिछले कई दशकों से अपेक्षित थीं। कृषि के लिए यह क्रांतिकारी बजट साबित हो सकता है, लेकिन तभी जब जो वायदे किए गए हैं उन्हें सही से पूरा किया जाए। किसानों के उत्पाद की उचित मूल्य पर खरीद की सरकारी प्रतिबद्धता और 10 करोड़ गरीब परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा की दिशा में पहली जरूरत थी। कहना न होगा कि इन 10 करोड़ गरीब परिवारों में किसान, मजदूर और निम्न आय वर्ग का बड़ा तबका शामिल होगा, लेकिन यहां एक पेंच है। सरकार ने किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने का जो वायदा इस बजट में किया है वह खरीफ की फसल से लागू होगा और इस साल खरीफ की उपज की खरीददारी लगभग खत्म हो चुकी है। लिहाजा यह

योजना अगली खरीफ से ही लागू हो सकेगी यानी आगामी नवंबर के आसपास। अगर मोदी सरकार समय से पहले चुनाव कराती है तो फिर वह अपना वायदा कब पूरा करेगी? जो सरकार की मंशा में विश्वास रखते हैं उनके अनुसार कोई भी सरकार जो चुनाव जीतना चाहती है वह किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती।

अगर सरकार आगामी रबी की फसल के दौरान भी अपने वायदे को पूरा करती है तो एक अनुमान के तहत इस पर कुल खर्च लगभग 60 हजार करोड़ रुपये आएगा। चुनाव पूर्व ऐसा खर्च किसी सरकार के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। रबी की फसल की खरीददारी आगामी अप्रैल माह से शुरू होनी है और कोई भी वायदा खिलाफी सरकार को बेहद महंगी पड़ सकती है। हालात ऐसे हैं कि सरकार किसानों की अनदेखी शायद ही कर पाए। यह उल्लेखनीय है कि बजट से पहले सामने

आये आर्थिक सर्वेक्षण में साफ तौर पर कहा गया है कि बीते चार सालों से किसानों की वास्तविक आय नहीं बढ़ी है। अच्छा होता कि सरकार को इसका भान पहले ही हो गया होता। पहली बार किसानों के उत्पाद के लिए लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने का संकल्प कृषि और किसानों की बेहतरी की दिशा में एक बड़ा कदम है। ध्यान रहे कि ऐसा वायदा 2014 के चुनाव के घोषणापत्र में भी किया गया था, लेकिन अगले ही वर्ष सरकार इससे मुकर गई और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में सरकारी पक्ष ने अपनी असमर्थता जता दी। जाहिर है कि विपक्षी दलों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और किसान भी संशुभित हुए। अगर सरकार 2014 में ही किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने को तैयार हो गई होती तो शायद उसे किसानों की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता। यही नहीं तब किसानों की बेचैनी इतनी अधिक नहीं बढ़ी होती और शायद उद्योग जगत को मंदी जैसी हालत से भी दो-चार नहीं होना पड़ता। चूंकि सरकार एक बार वायदा खिलाफी कर चुकी है इसलिए उसे इस बार बहुत सतर्कता बरतनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य वास्तव में मिले।

चूंकि अगले वर्ष आम चुनाव प्रस्तावित हैं इसलिए सरकार को कुछ ऐसे जतन करने ही होंगे जिससे इसी अप्रैल से शुरू होने वाले रबी की फसल की खरीददारी के दौरान लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने की योजना लागू हो सके। अगर ऐसा हुआ तो किसानों को पहली बार खेती मुनाफे का सौदा महसूस होगी। किसानों की फसल का लागत मूल्य तय करने का काम कृषि मूल्य एवं लागत आयोग करता है और वह इसे दो पैमाने के तहत करता है। इन्हें ए-2 और सी-2 नाम से जाना जाता है। स्वामीनाथन समिति की

रिपोर्ट के अनुसार सी-2 पैमाने पर लागत में किसान और उसके परिवार का श्रम और जमीन की कीमत भी शामिल होती है। अगर यह मान लिया जाए कि सरकार दूसरे प्रावधान यानी ए-2, जिसमें किसान का श्रम और जमीन की कीमत शामिल नहीं होती, के तहत करती है तो भी यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी। उदाहरण के तौर पर धान की कीमत सी-2 आधारित फॉर्मूले

जिस तरह सरकार किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना दाम देने के मामले में हीलाहवाली नहीं कर सकती, उसी तरह स्वास्थ्य बीमा योजना के मामले में भी कोई कोताही नहीं बरत सकती। इन दोनों वायदों को पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि इसके लिए पूरा तंत्र बनाने और उसके काम की गहन निगरानी करने की भी जरूरत पड़ेगी।

के अनुसार 1426 रुपये प्रति क्विंटल है और अगर इस पर 50 प्रतिशत बढ़ाकर समर्थन मूल्य तय किया जाए तो धान का समर्थन मूल्य लगभग 2139 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इतना ज्यादा मूल्य किसानों को आज तक नहीं मिला। इस गणना को अगर आगामी रबी और खासकर गेहूं की फसल पर लागू किया गया तो गेहूं का समर्थन मूल्य करीब 1900 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। उत्तर

भारत में बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए यह मूल्य एक तरह से वरदान साबित होगा। देखना है कि ऐसा होता है या नहीं?

प्रधानमंत्री ने जिस तरह बजट के बाद यह स्पष्ट किया कि लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण भारत के कल्याण पर खर्च किए जाएंगे उससे साफ है कि वह ग्रामीण इलाके के लोगों की बेचैनी को भांप चुके हैं। दरअसल सरकार के सामने आगे कुआं-पीछे खाई वाली स्थिति थी। अगर वह मध्यम और उच्च वर्ग को खुश करने के लिए आयकर और कॉरपोरेट कर में अपेक्षित छूट देती तो राजस्व कम आता। कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च करने का मतलब होता राजस्व घाटे में भारी बढ़ोतरी जो किसी भी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी ओर अगर सरकार किसानों और गरीबों के लिए अपना पिटारा न खोलती तो वे निराश-हताश तो होते ही, नाराज भी होते। सरकार ने दूसरा विकल्प चुना। इसी के तहत उसने स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रावधान रखा। अगर किसी गरीब का पांच लाख रुपये तक का इलाज सरकार की किसी योजना से मुफ्त होने लगे तो यह भारत में सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा कदम कहा जाएगा।

जिस तरह सरकार किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना दाम देने के मामले में हीलाहवाली नहीं कर सकती, उसी तरह स्वास्थ्य बीमा योजना के मामले में भी कोई कोताही नहीं बरत सकती। इन दोनों वायदों को पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि इसके लिए पूरा तंत्र बनाने और उसके काम की गहन निगरानी करने की भी जरूरत पड़ेगी। सरकार के सामने इस जरूरत को पूरा करने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं।

साभार: दैनिक जागरण

पीएमईजीपी आगे तीन वर्षों तक जारी रहेगी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को 5,500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 12वीं योजना से आगे तीन वर्षों के लिए 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना से तीन वित्तीय वर्षों में 15 लाख लोगों के लिए

रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) राष्ट्रीय स्तर पर नोडल क्रियान्वयन एजेंसी है।

समावेशी विकास हासिल करने के लिए देश के सभी जिलों को 75 परियोजना प्रति जिले का न्यूनतम लक्ष्य दिया गया है। सब्सिडी की ऊंची दर (25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत) महिलाओं अजा/जजा, अन्य

पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, ग्रामीण क्षेत्रों में एनईआर आवेदकों के लिए लागू होगी।

पीएमईजीपी 2008-09 से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा ऋण से जुड़ा प्रमुख सब्सिडी कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक दस्तकारों तथा ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।



महाराष्ट्र में किसानों ने दिखाया दम

सीपीआई (एम) के किसान संगठन ऑल इंडिया किसान संघ के बैनर तले लाल टोपी पहने और लाल झंडा थामे किसानों ने राज्य सरकार को घुटनों के बल झुका दिया। आखिरकार सरकार को उनकी सभी मांगें मानने का लिखित आश्वासन देना पड़ा। तब जाकर किसान अपने घरों को लौटे। इससे एक बात तय है कि लगभग खत्म हो चुके किसान आंदोलन को इससे नई जान मिली है कि अगर अन्नदाता चाहे तो कुछ भी हो सकता है।

महाराष्ट्र में हक की आवाज बुलंद करने के लिए 180 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके लगभग 50 हजार किसानों का सैलाब उतर आया। सीपीआई (एम) के किसान संगठन ऑल इंडिया किसान संघ (एआईकेएस) के बैनर तले लाल टोपी पहने और लाल बैनर थामे इन किसानों ने मुंबई की तरफ मार्च किया। इन किसानों का लक्ष्य 12 मार्च को विधानसभा का घेराव करना था। महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बना रहे थे। नासिक से मुंबई तक लॉन्ग मार्च पर निकले इन किसानों ने फड़नवीस सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में उग्र रूप धारण कर लिया।

पूरे परिवार के साथ मुंबई की तरफ मार्च कर रहे इन किसानों की मांग थी कि सरकार उनका बिजली का बकाया बिल माफ करे, किसानों का पूरा कर्ज माफ हो, फसलों की

वाजिब कीमत मिले और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। ये किसान सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे थे। सड़कों पर आक्रोशित किसानों की लंबी कतार दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ये विधानसभा का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। महाराष्ट्र सरकार को लगा कि भारी मुसीबत दरवाजे आ खड़ी हुई है। आखिरकार सरकार को इन आक्रोशित किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े। आखिरकार मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस द्वारा बनायी गयी छह सदस्यीय समिति को किसानों की ज्यादातर मांगें न सिर्फ माननी पड़ीं, बल्कि उन्हें मानने का लिखित आश्वासन भी देना पड़ा।

दूसरी तरफ किसानों के स्वागत में मुंबईवासियों ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। मुंबई के मशहूर डब्बेवालों ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। डब्बेवाला

एशोसिएशन का कहना था कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि जब वह आंदोलन करते हुए इतनी दूर से आये हैं तो हम उनके लिए भोजन का प्रबंध करें।

बता दें कि महाराष्ट्र लंबे समय से किसानों की समस्या से जूझ रहा है। हजारों किसान खुदकुशी कर चुके हैं। शिवसेना और भाजपा में तकरार का बड़ा मुद्दा भी किसान ही हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी अगले साल होंगे। ऐसे में किसानों को लगता है कि सरकार पर दबाव डालने का यह सही वक्त है। मौके की नजाकत को देखते हुए इस मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस को अपना अहं छोड़कर किसानों की मांग मानने की सलाह देकर पार्टी के इरादों का साफ संकेत दे दिया है। ●



SOUTH DELHI PUBLIC SCHOOL



FOUNDER SHRI G.S. RAWAT
(12 August 1914 – 6 June 1994)

Shri G.S. Rawat was a karmayogi with a deep passion for education. Shri Rawat won an intermediate scholarship after becoming the High School district topper. With a Bachelor of Science degree from Lucknow University, he joined the Ministry of Defence, Government of India, from where he took voluntary retirement as Deputy Director after a diligent career.

- Started in 1966 as a primary school (initially named Sharda Public School) in A-Block, Defence Colony, New Delhi by the South Delhi Education Society (Regd.).
- Encouraged with the performance of the school, in 1968 the school management succeeded in getting 1.978 acre land allotted at the present site.
- Upgraded as a Middle School (15 July 1972) with recognition from Directorate of Education, Delhi, the institute shifted to its new semi-constructed premises.
- The school was upgraded to the Secondary stage in 1982, and then to Senior Secondary stage in 1983. Finally, this sprawling three storeyed building with all facilities and amenities was completed.
- Managing Committee included representatives of Directorate of Education, teachers and parents are the guiding factotum of this institute.



SMT. URMILA RAWAT
Principal



SOUTH DELHI PUBLIC SCHOOL

D-Block, Defence Colony, New Delhi-110024

Phone: 011-47633333, 24629351

Email: sdpschooldefcol@gmail.com | Website: southdelhipublicschool.com



आज भारत, आज eNAM

NATIONAL AGRICULTURE MARKET

Reach More Markets

Real time information on trade and price

Extended access to markets across the state

Information on quality of commodities

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) नई सुविधाओं से लैस

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफार्म के इस्तेमाल को और अधिक आसान बनाने के लिए इसमें 6 नई विशेषताएं जोड़ी गयी हैं। ई-नाम योजना भारत सरकार की प्रमुख और महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों को उनकी उपज का ऑन-लाइन प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया है।

ई-नाम का मुख्य उद्देश्य अधिक पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है। किसानों के लिए कृषि वस्तुओं के विपणन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की परिकल्पना की गई थी और 14 अप्रैल, 2016 को इसे 21 मंडियों में शुरू किया गया था। अब तक 14 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश की 479 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं।

ई-नाम वेबसाइट अब आठ स्थानीय भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और ओड़िया) में उपलब्ध है तथा इस पर लाइव ट्रेडिंग सुविधा भी छह भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, मराठी और तेलुगु) में उपलब्ध कराई गई है।

कृषि मंत्रालय अब ई-नाम पोर्टल को नई

और यूजर फ्रेंडली सुविधाओं जैसे कि बेहतर विश्लेषण के लिए एमआईएस डैशबोर्ड, व्यापारियों को भीम एप द्वारा भुगतान की सुविधा, व्यापारियों को मोबाइल भुगतान की सुविधा, मोबाइल एप पर विस्तृत सुविधाएं जैसे कि गेट एंट्री और मोबाइल के जरिए पेमेंट, किसानों के डाटाबेस का एकीकरण, ई-नाम वेबसाइट में ई-लर्निंग माड्यूल आदि से लैस करते हुए और अधिक सुदृढ़ बना रहा है।

1) **ई-नाम मोबाइल एप** : मोबाइल एप का कई तरीके से संवर्धन किया जा रहा है ताकि किसानों और व्यापारियों के लिए सभी प्रक्रिया सुविधाजनक बन सके। मोबाइल एप को बहुभाषायी बनाया गया है। अब मंडी प्रचालकों (ऑपरेटर्स) द्वारा गेट एंट्री का महत्वपूर्ण कार्य सीधे ई-नाम मोबाइल एप से किया जा सकता है। इससे किसानों को मोबाइल एप पर अग्रिम रूप से गेट एंट्री करने की सुविधा उपलब्ध होगी और परिणामस्वरूप मंडी आने वाले किसानों का काफी समय बचेगा तथा गेट एंट्री और आवक सूचना आसानी से दर्ज की जा सकेगी। किसानों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है जिसमें वे अपनी फसल के क्रय-विक्रय तथा वास्तविक बोली प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी अपने मोबाइल एप पर प्राप्त कर सकेंगे।

अब व्यापारी (क्रेता) ई-नाम मोबाइल एप से डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। इससे खरीददारों के लिए धनराशि को एप के माध्यम से सीधे ट्रांसफर करना आसान होगा और व्यापारियों के लिए भी किसानों को ऑनलाइन भुगतान करना आसान हो जाएगा। किसान को उनके बैंक खाते में भुगतान प्राप्त होने के संबंध में एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा जिससे किसानों को भुगतान रसीद संबंधी सूचना मिल सकेगी।

2) **भीम एप से भुगतान सुविधा** : वर्तमान में ई-नाम पोर्टल किसानों को आरटीजीएस पेमेंट, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा देता है। भीम के जरिए यूपीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) सुविधा किसानों को भुगतान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे खरीददारों के एकाउंट से भुगतान लेकर उसे पूल अकाउंट में डालने तथा किसानों को भुगतान वितरण करने में लगने वाले समय में कमी आएगी।

3) **ई-लर्निंग माड्यूल सहित नवीन और समुन्नत वेबसाइट** : समुन्नत और अधिक सूचनापरक सुविधाओं जैसे कि गेट एंट्री पर ई-नाम मंडियों की वर्तमान स्थिति, नवीनतम घटनाओं की सूचना, डायनामिक ट्रेडिंग केलेंडर

आदि के साथ एक नई वेबसाइट विकसित की गई है। इसके अलावा, हिन्दी भाषा में ई-लर्निंग माड्यूल डिजाइन किया गया है और उसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, ताकि विभिन्न हित धारक इस सिस्टम को प्रयोग करने के बारे में ऑनलाइन तरीका सीख सकें और अपनी सुविधा अनुसार इस सिस्टम में लगातार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। वर्तमान में यह माड्यूल हिन्दी में उपलब्ध है।

4) एमआईएस डैशबोर्ड : बिजनेस इंटेलीजेंस आधारित एमआईएस डैशबोर्ड फसल की आवक और व्यापार के संबंध में प्रत्येक मंडी के कार्य निष्पादन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। इससे मंडी बोर्ड के अधिकारियों तथा मंडी सचिव को

प्रत्येक मंडी की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक तुलनात्मक कार्य निष्पादन की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इससे अधिकारी और मंडी सचिव जिंस व राज्य स्तर पर वास्तविक व्यापार विश्लेषण करने में समर्थ हो सकेंगे। इसके अलावा, मंडी बोर्ड और मंडी सचिव को अपने ऑपरेशन के पोस्ट ऐतिहासिक विश्लेषण और कार्य की योजना तैयार करने में भी मदद करेंगे।

5) मंडी सचिवों के लिए शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली : इस सिस्टम द्वारा मंडी सचिव को पोर्टल/सॉफ्टवेयर और उसके प्रचालन से संबंधित तकनीकी मुद्दे उठाने तथा उनके प्रश्नों के निवारण की ऑनलाइन निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

6) किसान डेटाबेस का एकीकरण : ई-नाम को सेंट्रल फार्मर डेटाबेस के साथ जोड़ा गया है ताकि पंजीकरण की प्रक्रिया ज्यादा आसान हो सके तथा मंडी गेट पर आवक के दौरान किसान की पहचान आसानी से की जा सके। इससे गेट एंट्री स्तर पर कार्यक्षमता बढ़ेगी और कतार समय (क्यू टाइम) में भी कमी आएगी। इसके अलावा, रबी और खरीफ की अधिक आवक के समय अधिक कार्य क्षमता के साथ गेट स्तर पर लोड को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी और एंट्री गेट पर किसानों के अपनी उपज के साथ प्रतीक्षा करने के समय में कमी आएगी। कुल मिलाकर राष्ट्रीय कृषि बाजार से एक पारदर्शिता आएगी। ●

राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन ने 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी

राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति की नौवीं बैठक में करीब 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश में कानपुर के जाजमऊ स्थित चमड़ा शोधन कारखानों के लिए 20 एमएलडी सार्वजनिक अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र शामिल हैं। 629 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली तीन चरणों की इस परियोजना में 380 अलग-अलग चमड़ा शोधन इकाइयों में पूर्व शोधन इकाई, एक 20 सीईटीपी होगा, जिसमें प्राकृतिक, जैविक और उन्नत शोधन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) आधारित 200 केएलडी क्षमता का प्रमुख संयंत्र होगा। इस परियोजना में केन्द्र की हिस्सेदारी 472 करोड़ रुपए है। कानपुर औद्योगिक शहर से गंगा में होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए यह एक प्रमुख कदम है। इस परियोजना को विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) जाजमऊ चमड़ा शोधन एसोसिएशन द्वारा अमल में लाया जाएगा।

कानपुर के जाजमऊ, बिनगवां, साजरी में सीवेज शोधन बुनियादी ढांचे के पुनर्वास और समेकन के लिए हाइब्रिड एन्युईटी-पीपीपी मोड के अंतर्गत 967.23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक अन्य परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में पंखा

में 30 एमएलडी एसटीपी का निर्माण शामिल है। केंद्र सरकार पूंजीगत निवेश और 15 वर्ष संचालन तथा रखरखाव करेगी। इलाहाबाद में नैनी, सलारी, नुमायादही, राजापुर, पोन्घाट, पोडरा सीवेज क्षेत्रों में सीवेज शोधन बुनियादी ढांचे के पुनर्वास और समेकन के लिए हाइब्रिड एन्युईटी-पीपीपी मोड के अंतर्गत 904 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए सभी एसटीपी और एसपीएस के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को भी मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार पूंजीगत निवेश और 15 वर्ष संचालन तथा रखरखाव करेगी।

गंगा नदी में जाने वाले नालों के मूल स्थान से दूर जैव उपचारात्मक शोधन की एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिस पर अनुमानतः 410 करोड़ रुपए लागत आएगी। एनएमसीजी ने सीपीसीबी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए प्रदूषण फैलाने वाले अन्य प्रमुख नालों की पहचान की है, जो मुख्य पाइप में जाकर मिल जाते हैं। यहां टेक्नोलॉजी सेवा प्रदाता गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए कंटेनराइज्ड माॅड्यूलर शोधन संयंत्रों सहित शोधन सुविधाएं स्थापित करेंगे। पहचान गए नालों को इसके बाद प्राथमिकता वाले नालों में वर्गीकृत किया गया है। परियोजना के पहले चरण में शोधन के लिए 20 नालों को ध्यान में रखा गया

है। बुनियादी ढांचे के विकास की अंतरिम अवधि के लिए नालों में प्रदूषण के दबाव का प्रबंध करने के लिए मूल स्थान पर के बाहर तेजी से तकनीकी-आर्थिक और सतत टेक्नोलॉजी अपनाने तथा गंगा नदी में सीधे सीवेज छोड़े जाने के संचयी प्रभाव के प्रबंध के लिए यह कदम उठाया गया है। यह समग्र दृष्टिकोण नमामि गंगे कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया है, ताकि गंगा नदी में सीवेज का प्रवाह रोका जा सके।

पश्चिम बंगाल में हाइब्रिड एन्युईटी मोड के अंतर्गत गार्डन रीच एसटीपी (57 एमएलडी) और केवड़ापुकुर एसटीपी (50 एमएलडी) के लिए 15 वर्ष के संचालन और रखरखाव के साथ पुनर्वास की एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस पर 165.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। केंद्र सरकार पूंजीगत निवेश और 15 वर्ष संचालन तथा रखरखाव करेगी।

बिहार में बेगुसराय, हाजीपुर और मुंगेर में तीन सीवेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को क्रमशः 230.06 करोड़ रुपए, 305.18 करोड़ रुपए और 294.02 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की संशोधित मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में केन्द्र की हिस्सेदारी क्रमशः 161.04 करोड़ रुपए, 213.63 करोड़ रुपए और 205.81 करोड़ रुपए होगी। केंद्र सरकार पूंजीगत निवेश और 15 वर्ष संचालन तथा रखरखाव करेगी। ●



MADE EASY

India's Best Institute for IES. GATE & PSUs

ABOUT MADE EASY

MADE EASY – a name synonymous for success in ESE, GATE & PSUs exams, is more than a decade old success partner of engineering graduates for written examinations and personality tests, which are integral to the selection process. MADE EASY has maintained its exclusivity by consistently producing toppers and highest number of good rank holders in ESE, GATE and PSUs right since its inception in the year 2001. The Endeavour was taken up as a challenge improvising techniques of learning each year to yield best results.

Dynamic Leadership

MADE EASY is headed under the dynamic leadership of Mr. B. Singh (Ex. IES). An alumnus of IIT-BHU, who had qualified IES exam thrice, was selected for GATE and PSUs, having more than 15 years of experience in imparting quality education to students for various competitive exams and was conferred with many awards like, Education Excellence, Captains of Industry Award, Best Entrepreneur promoting Education Award for IES, GATE and PSUs given by Hon'ble Governor of Gujarat. MADE EASY has recently been conferred with National Education Excellence Award-2015 by the Hon'ble Chairman, AICTE. Mr. B. Singh is also a member of Indian Society of Technical Education, Indian Road Congress & Indian Geo-technical Society.

Synonym for Quality Teaching

MADE EASY has best pool of faculty who are permanent & their only intent is to provide quality education to the students. MADE EASY has a perfect combination of professors and young & energetic top rankers of ESE & GATE.

MADE EASY's 6 point Success Mantra

- Consistent, focused, systematic and well- coordinated course curriculum
- Thoroughly revised, updated and relevant study material
- Tireless efforts of experts and committed faculty members to achieve timely completion of syllabus
- Highly proficient & experienced faculty members
- Exclusive and extensive personality development program
- Regular assessment of performance through test series

Well designed, Fully Revised and Comprehensive Study Material/ Books

MADE EASY provides its students with comprehensively designed study material that gives students conceptual clarity and command over topics ensuring understanding of even the most difficult topics. It includes easy explanations, simple examples and other research-proven techniques of study material presentation. At regular intervals study material is thoroughly revised and a new set of questions are added.

Complete Guidance for written and Personality Development scientifically

MADE EASY also emphasizes on the importance of Personality Development along with complete focus on academics. MADE EASY periodically conducts a Comprehensive Interview Guidance Program by Personality Development Experts. MADE EASY frequently organizes Motivational and Personality Development Sessions to prepare the students for interviews and writing skills.

Pan India Presence

MADE EASY has a Pan-India presence having centres in Delhi, Noida, Hyderabad, Bhopal, Jaipur, Lucknow, Indore, Bhubaneswar, Kolkata, Pune and Patna that offer career guidance through Classroom and Postal Coaching Programs in all core engineering branches.

Highest Selections with Top Rankers

MADE EASY is the only institute which has consistently produced maximum number of toppers in IES, GATE & PSUs.

MADE EASY GROUPS OF INSTITUTIONS

1) MADE EASY Publications

The Publication vertical of MADE EASY was established in 2007 to further MADE EASY's objective of excellence in education by publishing quality and authentic books. MADE EASY Publications is head quartered at Delhi. The books are available at all leading books stores and at online platforms across the country.

www.madeeasypublications.org

2) MADE EASY FOR YOU: A Charitable Trust

MADE EASY FOR YOU is a charitable trust of MADE EASY Group. Being the trustee of MADE EASY FOR YOU, Mr. B. Singh is very generous in social causes. Either it is a matter of Flood victims or affected farmers, MADE EASY has donated lacs of money to help the victims and extended all possible help to provide relief to the affected people.

www.madeeasyforyou.in

3) MADE EASY PRESCHOOL

First school for a child is the most important thing for any par-

ent and you could put them on a path towards lifelong learning. At MADE EASY preschool, learning is engaging, interesting and enjoyable, and children learn by discovering things on their own. Our approach to education is child-centric, so that they are in love with learning all through life. We are committed to provide early childhood education with world class facilities, best teaching practices such as an inquiry-based learning. We cater to the growing segment of quality conscious parents, who desire a holistic experience in the formative years of their child's life. We have best Child teacher ratio for optimal care and attention.

www.madeeasypreschool.in

WHY MADE EASY

1) Comprehensive Coverage

- In-depth coverage of syllabus (both Tech. and Non-tech) with prime focus on fundamental concepts.
- Gradual transition from basic to advance level making it duck soup for fresher.

2) Excellent Pool of Faculties

- Hub of country's most intellectual engineer faculties, combination of both experienced seniors and vibrant young top rankers of ESE and GATE.

3) Professionally Managed and Structured Organization

- Pre-planned class schedule, with accurate implementation of time-table.
- Well-skilled management staff and faculties, serving with full dedication and commitment.

4) Timely Completion of Syllabus

- Well framed modules under tutelage of Mr. B. Singh, CMD for early syllabus completion, giving ample time for revision; we believe in "Revision is necessary for Retention."

5) Focused and Comprehensive Study Books

- Detailed but relevant to exam, so that need for second book doesn't arise.
- Thoroughly revised and updated study material, by qualified R & D team of MADE EASY.

6) Regular Assessment of Performance

- GATE online test series.
- ESE All India classroom test series.
- Subject-wise classroom tests with discussion.

- Test environment similar to GATE and UPSC.

7) Interactive Classrooms and Infrastructure

- We believe in "See and Learn" – we have best quality teaching tools with equipped audio-visual classrooms.

8) Regular update on Vacancies/Notifications

- Vacancies of govt. departments and exam notifications of GATE, ESE, PSUs and State Services exam are displayed on notice board and announced in class without fail.

9) Complete Guidance for Written and Personality Test

- Industrious team of MADE EASY, provides year round mentoring for
 - Interpersonal Skills
 - Communication Skills
 - GD and Psychometric Skills
 - Mock Interviews

10) Motivational and Counseling Seminars

- Career counseling by all expert teachers.
- Sessions on techniques for efficient learning.
- Motivational sessions by experts and ESE/GATE toppers.

11) Post Exam Support

- Guidance for M.Tech Admission.
- Interview guidance for ESE and PSUs.

12) Astonishing Results

- MADE EASY, needless to say has made it EASY thereby, has consistently produced toppers and also maximum number of selections in GATE and ESE.

FOR MORE DETAILS PLEASE CONTACT

- **Delhi** : 011-45124612, 09958995830, 09810541651
- **Patna** : 0612-2356615, 0612-2356616, 9955991166
- **Lucknow** : 09919111168, 08400029422
- **Jaipur** : 0141-4024612, 09166811228
- **Bhopal** : 0755-4004612, 08120035652
- **Indore** : 0731-4029612, 07566669612
- **Pune** : 020-26058612, 09168884343
- **Hyderabad** : 040-66774612, 040-24652324
- **Bhubaneswar** : 0674-6999888, 09040999888
- **Kolkata** : 033-68888880, 08282888880
- **Noida** : 0120-6524612, 08860378009

Visit us: <https://madeeasy.in>

एक्वाकल्चर में रोजगार के अवसर

एक्वाकल्चर से लेकर मछलियों की समुद्री खेती, सीपदार मछली और समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के बहुत से विकल्प मौजूद हैं।

■ डॉ. अरुण एस. निनावे

मछली पालन कृषिक्षेत्र के तहत एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है, जो लाखों लोगों के लिए प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के रूप में उपलब्ध है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसका करीब 1.4 प्रतिशत और एक्वाकल्चर क्षेत्र में कुल मिलाकर जीडीपी का 4.5 प्रतिशत योगदान है। व्यापक संदर्भ में इसमें अंतर्देशीय और समुद्री, एक्वाकल्चर, सामग्रियां, नौवहन, महासागर विज्ञान, मछलीघर प्रबंधन, मत्स्य प्रजनन, प्रसंस्करण, समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात और आयात, विशेष उत्पादन और अन्य उत्पाद, अनुसंधान तथा संबद्ध गतिविधियां शामिल होती हैं। भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और अंतर्देशीय मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जैव विविधता से परिपूर्ण भारत के लंबे तटीय क्षेत्र के कारण यहां मछलियों की एक्वा-फार्मिंग और मनोरंजन अथवा उपभोग के लिए क्रसटेशियन तथा पानी में पैदा होने वाले पौधे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस पर गरीब मछुआरा समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए निर्भर होने के कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है।

यह अत्यधिक क्षमतावान क्षेत्र है जिसमें एक्वाकल्चर और मेरीकल्चर फार्मिंग व्यवहारों के जरिये मछली पालन के विकास के व्यापक अवसर मौजूद हैं। पिछले छह दशकों के दौरान इस क्षेत्र को अत्यधिक अपेक्षित तकनीक, मानव शक्ति और सक्षम विस्तार

कार्मिकों और प्रभावी प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ विकसित किया गया है। अनुसंधान और विकास ने जलजीव विज्ञानियों, फार्म प्रबंधकों, निर्यातकों, व्यापारियों, प्रजनकों और आधुनिक मछुआरों को शामिल करते हुए इस क्षेत्र के उत्पादन स्तर में सुधार और खेती के लिए मत्स्य बीज, उच्च उत्पादक नस्ल और दवाई की उपलब्धता में सराहनीय सहयोग दिया है। अत्यधिक लाभप्रद क्षेत्र होने के कारण इसे मछली पालन और जलीय विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में रोजगार के अवसरों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है।

मत्स्य विज्ञान में प्रवेश हेतु पात्रता

मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रवेश पाने के वास्ते मात्स्यिकी स्नातक बनने के इच्छुक व्यक्तियों को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के मात्स्यिकी महाविद्यालयों से 4 वर्षीय डिग्री उत्तीर्ण करनी होती है। मात्स्यिकी विज्ञान में बैचलर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और बायो ग्रुप रखने वाले व्यक्ति 10+2 के उपरांत आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को मैरिट स्कोर और सीटों की उपलब्धता के अनुसार प्रवेश प्रदान किया जाता है। राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को विशेष कोटे की अनुमति होती है जिन्होंने कृषि अनुसंधान परिषद की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की होती है और अध्येतावृत्ति भी प्राप्त कर रहे होते हैं। इसमें जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए विशेष आरक्षित सीटें होती हैं। मात्स्यिकी विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में अंतर्देशीय



राष्ट्रीय/राज्य मात्स्यिकी संस्थान

1. केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, वर्सावा, मुंबई, www.cif.edu.in
2. केंद्रीय खारा पानी जलजीव संस्थान, चेन्नई, www.ciba.res.in
3. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ, www.nbfgr.res.in
4. केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कोच्चि, www.cifnet.nic.in
5. तमिलनाडू फिशरीज यूनिवर्सिटी, नागपट्टिनम, तमिलनाडु, www.tnfnu.org.in
6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर, पश्चिम बंगाल, www.iitkgp.ac.in
7. आंध्र विश्वविद्यालय, तेलीबाग, वाल्टेर, आंध्र प्रदेश, www.andhrauniversity.edu.in
8. गोआ विश्वविद्यालय, www.unigoa.ac.in

राज्य कृषि/पशुचिकित्सा विश्वविद्यालयों के अधीन मात्स्यिकी माहविद्यालय

1. कॉलेज ऑफ फिशरीज, शिरगांव, रत्नागिरी, www.dbskkv.org
2. मात्स्यिकी विज्ञान माहविद्यालय, तेलंगखेडी, नागपुर, <http://cofsngp.org>
3. कॉलेज ऑफ फिशरीज मंगलौर, कर्नाटक, www.kvafsu.kar.nic.in
4. कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस, पंतनगर, उत्तर प्रदेश, www.gbpuat.ac.in
5. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, www.pau.edu
6. इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, थिरुवल्लूर, चेन्नई, <http://iftponneri&tnfnu.org>
7. कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस, कुलिया, पश्चिम बंगाल, www.wbuafsc.ac.in
8. कॉलेज ऑफ फिशरीज, वेरावल, गुजरात, <http://www.gsauca.in>

एक्वाकल्चर, फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर, मेरीकल्चर, औद्योगिक मत्स्यपालन, मछली प्रसंस्करण और फसल उपरांत प्रौद्योगिकी, मत्स्य पोषण, पैथोलॉजी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विस्तार जैसे विषय शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम में व्यवहारिक अनुभव भी शामिल होता है, जैसे कि समुद्री नौकाओं पर मछली पकड़ना और डाटा संग्रह तथा प्रसंस्करण संयंत्रों में मात्स्यिकी आदि। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शैक्षणिक कार्यक्रम के जरिये ग्रामीण कृषि कार्यानुभव (आरएडब्ल्यू) के अधीन फार्म अध्ययनों से छात्रों को एक्वा-फार्मों, हैचरी, मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों, मूल्यवर्द्धन, संसाधन प्रबंधन आदि पर व्यावहारिक ज्ञान हासिल करने में सहायता मिलती है।

उच्चतर शिक्षा

मत्स्य विज्ञान में बैचलर डिग्री पूर्ण करने के उपरांत उम्मीदवार मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को चुन सकते हैं जिसके लिए भारत में केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित आठ मात्स्यिकी संस्थान हैं, जिनके नाम हैं- सीआईएफई, सीआईबीए, सीआईएफए, सीएमएफआरआई, सीआईएफटी, सीआईएफआरआई, एनबीएफजीआर और डीसीएफआर। ये संस्थान अपने अनुसंधान कार्यक्रम के अलावा मछली पकड़ने, खेती, मूल्य विस्तार प्रसंस्करण, संग्रह, संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन संस्थानों में छात्र स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर तक की विशेषीकृत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा स्वतंत्र पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विद्यालयों के अधीन करीब 18 मात्स्यिकी महाविद्यालय और राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी मात्स्यिकी विज्ञान में बैचलर तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। अवसंरचना और अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर मात्स्यिकी महाविद्यालय अपनी व्यवस्था के अधीन पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। कई विद्यालयों के जरिये जलजीव विज्ञान और मात्स्यिकी में मास्टर और पीएचडी कार्यक्रम उपलब्ध है। छात्र अपनी रुचि के अनुरूप अनुसंधान का विषयक्षेत्र चुन सकते हैं, जैसे कि मत्स्य पोषण, जल गुणवत्ता, जलजीव विज्ञान इंजीनियरिंग, मछली आनुवंशिकी, अंडा उत्पादन और मत्स्य

पैथोलॉजी। ज्यादातर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शोधपत्र अपेक्षित होते हैं जबकि पीएचडी छात्रों के लिए मुख्यतः एक पूर्ण शोध-निबंध अपेक्षित होता है। मछली पालन और प्रजनन, एकीकृत मत्स्य-पशुधन फार्मिंग, मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन और पोषण, सघन मत्स्य फार्मिंग तथा पर्यावरण प्रबंधन और प्रसंस्करण के विकास जैसे क्षेत्रों में शोध गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

मात्स्यिकी स्नातक और उच्चतर अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को आकर्षक वेतन और लाभों के साथ अच्छे रोजगार अवसर प्राप्त होते हैं। सरकारी संस्थानों में उन्हें सहायक निदेशक, अनुसंधान सहायक और मात्स्यिकी निरीक्षक आदि के तौर पर नियुक्त किया जाता है।

कौशल आधारित प्रशिक्षण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र अपने संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं और एनसीईआरटी से सक्रिय सहयोग से 10+2 स्तर पर मत्स्य पालन को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तौर पर शामिल करते हैं। तटीय राज्यों में मछुआरा बहुल गांवों में मछुआरों के लिए नियमित कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नोटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग (सीआईएफएनईटी) द्वारा भी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा नौवाहन विषय पर प्रशिक्षण संचालित किये जाते हैं। भारत में विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्कूबा डाइविंग में लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं जिनसे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और संसाधन उपयोग, मानचित्रिकरण तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में रोजगार सृजन में सहायता मिलती है।

रोजगार के अवसर

मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर स्नातकों के लिए विभिन्न विशेषताओं के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं जिनमें राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां, अकादमिक संस्थान

तथा मछली फार्म शामिल हैं। सरकारी एजेंसियां और उद्योग संगठन एक्वाकल्चर कृषक, सीपदार मछली कृषक, हैचरी तकनीशियन, जैविकीय विज्ञान तकनीशियन, मछली अनुसंधान सहायक आदि जैसे पदों पर भर्ती करते हैं। एक्वाकल्चर से लेकर मछलियों की समुद्री खेती, सीपदार मछली और समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के बहुत से विकल्प मौजूद हैं। प्राथमिक स्तर के एक्वाकल्चर रोजगारों के लिए हाई स्कूल डिप्लोमा अथवा एक्वाकल्चर एवं मात्स्यिकी में अंडर-ग्रेजुएट डिग्री अपेक्षित होती है परंतु अधिक उन्नत पदों के लिए स्नातकोत्तर अथवा पीएचडी डिग्री की आवश्यकता होती है। राज्य सरकारों में मछली पालन विभाग में मात्स्यिकी स्नातकों के लिए सहायक मात्स्यिकी विकास अधिकारी तथा मात्स्यिकी विकास अधिकारी और जिला मात्स्यिकी विकास अधिकारी के पद उपलब्ध होते हैं।

एक्वाकल्चर रोजगारों के लिए ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए विदेशों में मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर में एसोसिएट और बैचलर डिग्री कार्यक्रम उपलब्ध करवाये जाते हैं। द्विवर्षीय कार्यक्रमों में छात्र स्नातक के उपरांत रोजगार बाजार में प्रवेश के लिए अनुप्रयुक्त विज्ञान डिग्री के एसोसिएट के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और इसे चार वर्षीय अकादमिक कार्यक्रम में तब्दील करने के लिए विज्ञान में फेलोशिप हासिल कर सकते हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और यूरोपीय देशों आदि में मात्स्यिकी में उच्चतर शिक्षा के लिए संभावना के अलावा, खाड़ी और अफ्रीकी देशों में भी एक्वाकल्चर तथा प्रसंस्करण क्षेत्रों में मात्स्यिकी विशेषज्ञों की मांग है। विदेशों में एक्वाकल्चर, निर्यात और आयात के क्षेत्र में व्यापार संचालित करने वाले बहुत से मात्स्यिकी स्नातक मौजूद हैं।

मात्स्यिकी स्नातक और उच्चतर अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को आकर्षक वेतन और लाभों के साथ अच्छे रोजगार अवसर प्राप्त होते हैं। सरकारी संस्थानों में उन्हें सहायक निदेशक, अनुसंधान सहायक और मात्स्यिकी निरीक्षक आदि के तौर पर नियुक्त किया जाता है। निजी क्षेत्र में मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, मत्स्य प्रोसेसर, एक्वाकल्चररिस्ट, फार्म सहायक, प्रबंधक आदि के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ●



सस्ता विकल्प है हरी खाद

■ कृषि चौपाल

मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाये रखने के लिए हरी खाद एक सस्ता विकल्प है। सही समय पर फलीदार पौधे की खड़ी फसल को मिट्टी में ट्रैक्टर से हल चलाकर दबा देने से जो खाद बनती है उसको हरी खाद कहते हैं। आदर्श हरी खाद में निम्नलिखित गुण होने चाहिए—

- उगाने का न्यूनतम खर्च
- न्यूनतम सिंचाई आवश्यकता
- कम से कम पादम संरक्षण
- कम समय में अधिक मात्रा में हरी खाद प्रदान कर सकें
- विपरीत परिस्थितियों में भी उगने की क्षमता हो
- जो खरपतवारों को दबाते हुए जल्दी बढ़त प्राप्त करे
- जो उपलब्ध वातावरण का प्रयोग करते हुए अधिकतम उपज दे।

हरी खाद बनाने के लिए अनुकूल फसलें

- ढेंचा, लोबिया, उरद, मूंग, ग्वार बरसीम, कुछ मुख्य फसले हैं जिसका प्रयोग हरी खाद बनाने में होता है। ढेंचा इनमें से अधिक प्रचलित है।
- ढेंचा की मुख्य किस्में सस्बेनीया ऐजिप्टिका, एस रोस्ट्रेटा तथा एस एक्वेलेटा अपने त्वरित खनिजकरण पैटर्न, उच्च नाइट्रोजन मात्रा तथा कम कार्बन-नाइट्रोजन अनुपात के कारण बाद

में बोई गई मुख्य फसल की उत्पादकता पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने में सक्षम है।

हरी खाद के पौधों को मिट्टी में मिलाने की अवस्था

- हरी खाद के लिये बोई गई फसल 55 से 60 दिन बाद जोत कर मिट्टी में मिलाने के लिये तैयार हो जाती है।
- इस अवस्था पर पौधे की लंबाई व हरी शुष्क सामग्री अधिकतम होती है 55 से 60 दिन की फसल अवस्था पर तना नरम व नाजुक होता है जो आसानी से मिट्टी में कटकर मिल जाता है।
- इस अवस्था में कार्बन-नाइट्रोजन अनुपात कम होता है, पौधे रसीले व जैविक पदार्थ से भरे होते हैं इस अवस्था पर नाइट्रोजन की मात्रा की उपलब्धता बहुत अधिक होती है
- जैसे जैसे हरी खाद के लिये लगाई गई फसल की अवस्था बढ़ती है कार्बन-नाइट्रोजन अनुपात बढ़ जाता है, जीवाणु हरी खाद के पौधों को गलाने-सड़ाने के लिये मिट्टी की नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं। जिससे मिट्टी में अस्थायी रूप से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है।

हरी खाद बनाने की विधि

- अप्रैल-मई माह में गेहूं की कटाई के बाद जमीन की सिंचाई कर लें। खेत में खड़े पानी में 50 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से ढेंचा का बीज छितरा लें।

- जरूरत पढ़ने पर 10 से 15 दिन में ढेंचा फसल की हल्की सिंचाई कर लें।
- 20 दिन की अवस्था पर 25 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से यूरिया को खेत में छितराने से नोड्यूल बनने में सहायता मिलती है।
- 55 से 60 दिन की अवस्था में हल चलाकर हरी खाद को पुनः खेत में मिला दिया जाता है। इस तरह लगभग 10-15 टन प्रति हैक्टेयर की दर से हरी खाद उपलब्ध हो जाती है। जिससे लगभग 60-80 किलो नाइट्रोजन प्रति हैक्टेयर प्राप्त होता है। मिट्टी में ढेंचे के पौधों के गलने-सड़ने से बैक्टीरिया द्वारा नियत सभी नाइट्रोजन जैविक रूप में लंबे समय के लिए कार्बन के साथ मिट्टी को वापस मिल जाते हैं।

हरी खाद के लाभ

- हरी खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार होता है।
- हरी खाद से मृदा उर्वरता की भरपाई होती है।
- पोषण के लिए आवश्यक तत्वों को बढ़ाता है।
- सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है।
- मिट्टी की संरचना में सुधार होने के कारण फसल की जड़ों का फैलाव अच्छा होता है।
- हरी खाद के लिए उपयोग किये गये फलीदार पौधे वातावरण से नाइट्रोजन व्यवस्थित करके नोड्यूलस में जमा करते हैं जिससे भूमि की नाइट्रोजन शक्ति बढ़ती है।
- हरी खाद के लिये उपयोग किये गये पौधे को जब जमीन में हल चलाकर दबाया जाता है तो उनके गलने-सड़ने से नोड्यूलस में जमा की गई नाइट्रोजन जैविक रूप में मिट्टी में वापस आ कर उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है।
- पौधों के मिट्टी में गलने-सड़ने से मिट्टी की नमी के जलधारण की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। हरी खाद के गलने-सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि मिट्टी से आवश्यक तत्व को मुक्त कराकर मुख्य फसल के पौधों को आसानी से उपलब्ध करवाती है।
- हरी खाद दबाने के बाद बोई गई धान की फसल में ऐकिनोक्लोआ जातियों के खरपतवार न के बराबर होते हैं जो हरी खाद के ऐलेलोकेमिकल प्रभाव को दर्शाते हैं।

AMAN PUBLIC SCHOOL

Aspiring International School

Dhalwala, Rishikesh, Uttarakhand

It is on the steps of an International School for quality education and well planed outdoor activities within nature areas.

At present:

- It is popular among the farming community
- Local employees
- Small businessman and traders
- Migrated people from other states
- We have well educated teaching staff
- Natural and homely environment for young learners

We are making it well-developed, quality-oriented cosmopolitan school without any discrimination. The local population is very much happy and satisfied with the education provided to their children at the very nominal fees.

Our school is dedicated to complete development of the students.



Shri U. S. Panwar is a social activists, philanthropist, statesman of national standard. For the last forty years he has been helping needy and helpless people in the country. He has worked and aided several environmental, educational and other development projects in Himachal and Uttarakhand region. All his wit and wisdom is working for building an advanced nation. In Dehradun, his Aman Public School is providing education to poor and helpless children for the past several years.

Contact: 9868101623



विदेशी सब्जियों की खेती से मालामाल हो रहे पंजाब के ये 'मॉडर्न' किसान

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के प्रतिष्ठित उजागर सिंह धालीवाल अवार्ड और मुख्यमंत्री सम्मान से सम्मानित पटियाला के साहौली गांव के किसान मेहरबान सिंह सब्जियों की संरक्षित खेती में लगे हुए हैं। सब्जियों की संरक्षित खेती की विधि से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों मसलन बुआई के तरीकों, कीटनाशकों के छिड़काव आदि को लेकर मेहरबान सिंह निरंतर कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने लंदन की यात्रा के दौरान उन्होंने सब्जियों के बाजार जाकर सब्जियों के निर्यात से संबंधित बारीकियों को समझने की कोशिश की। उपज और उससे होने वाली आय दोनों ही मामलों में प्रति इकाई जल उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करके अनाज की एकल कृषि (मोनोकल्चर) छोड़कर उन्होंने सब्जियों की खेती करने का फैसला किया। सब्जियों को उपजाने के लिए बड़ी संख्या में विकल्पों की उपलब्धता को देखते हुए वे आवश्यकतानुसार खेत और फसल का चयन बारी-बारी से करते हैं ताकि

मिट्टी की पोषण क्षमता और स्वास्थ्य पर दबाव कम रहे। अपने सभी खेतों में सिंचाई के लिए उन्होंने ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली लगा रखी है। ड्रिप प्रणाली की मदद से ही वे खेतों में उर्वरकों का भी छिड़काव करते हैं। ड्रिप प्रणाली के साथ ही वे फसलों के लिए पलवार पद्धति (फसल की जड़ को जैविक खाद से बांधने) का प्रयोग करते हैं जिससे न केवल पानी की बचत होती है बल्कि खेतों में खरपतवारों के नियंत्रण में भी मदद मिलती है। अपने खेतों में उन्होंने एक कुएं का भी निर्माण करा लिया है ताकि भूमिगत जल के स्तर को बरकरार रखा जा सके और नहरों से बहकर आने वाले पानी को बर्बादी से बचाया जा सके। सब्जियों पर आधारित विविध खेती को अपनाकर उन्होंने अपने आय में परंपरागत खेती की तुलना में तीन गुनी बढ़ोत्तरी कर ली है।

मेहरबान सिंह की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए देश में उर्वरकों की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको ने भी उन्हें 20,000 रुपये की मदद की। आप इन्हें

टमाटर, हरी मिर्च, बीज रहित खीरा, करेला और लौकी जैसी सब्जियां उपजा कर देविंदर और मेहरबान प्रति एकड़ सत्तर से अस्सी हजार रुपये तक की आमदनी करते हैं जबकि दिसंबर से फरवरी के बीच ठंड और पाले से बचाने के लिए पॉली हाउसेज और लो टनल प्रौद्योगिकी के जरिए शिमला मिर्च उपजा कर इनको चार से पांच लाख प्रति एकड़ की आमदनी हो जाती है।

पंजाब की 'नई फसल' कह सकते हैं, पंजाब के ये किसान अपनी उपज का दुनिया भर में विपणन भी कर रहे हैं।

ऊंचे दामों में बिकने वाली सब्जियां जैसे टमाटर, करेला और लौकी को कॉरपोरेट तरीके से उपजाने और बेचने के बाद पंजाब में किसान पीले और लाल मिर्च और बीज रहित खीरा जैसी विदेशी फसल की ओर भी रुख कर रहे हैं। यही नहीं, पंजाब के सब्जी उत्पादक इलाके लुधियाना, पटियाला, जालंधर और फतेहगढ़ साहिब जिलों के तकरीबन 50 प्रगतिशील किसानों ने गुणवत्तापूर्ण शाकाहारी उत्पाद के लिए एक मंच बनाया है जिसके जरिए ये किसान अपनी सब्जियों का विपणन, जिनके उपज के दौरान तयशुदा प्रमाणिक मानकों के अनुरूप उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया गया है, खेती में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, खुदरा विक्रेताओं से मोल-भाव करने, संभावित देशी-विदेशी बाजार की तलाश करने के लिए करते हैं।

परंपरागत खेती करने वाले लुधियाना के समराला जिले के मुश्काबाद के देविंदर सिंह और पटियाला जिले के नाभा के रहने वाले मेहरबान सिंह को विदेशी और ऊंची कीमत वाली सब्जियों का मोल समझने में छह से सात साल लग गए। ब्रिटेन में रहने वाले एमबीए डिग्रीधारी सिकंदर तवाना ने जब 2008 में उनके फार्म का दौरा किया तो उन्होंने भी इनकी सफलता को अपने खेतों में दोहराने का संकल्प लिया। यहीं से इन्होंने एक सामूहिक मंच बनाने का फैसला

किया। तीनों ने इसके लिए राज्य के और भी सब्जी उत्पादकों और एंव एनआरआई कृषकों के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण शाकाहारी उत्पादकों के लिए एक कंपनी की शुरुआत की। दो सालों में कंपनी में सदस्यों की संख्या 50 तक पहुंच गई जिसमें अमेरिका में रहने वाले उदय पाल सिंह जैसे कृषक भी शामिल हैं जो पंजाब के पटियाला स्थित सनयार खेड़ी गांव स्थित अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं।

टमाटर, हरी मिर्च, बीज रहित खीरा, करेला और लौकी जैसी सब्जियां उपजा कर देविंदर और मेहरबान प्रति एकड़ सत्तर से अस्सी हजार रुपये तक की आमदनी करते हैं जबकि दिसंबर से फरवरी के बीच ठंड और पाले से बचाने के लिए पॉली हाउसेज और लो टनल प्रौद्योगिकी के जरिए शिमला मिर्च उपजा कर इनको चार से पांच लाख प्रति एकड़ की आमदनी हो जाती

है। देविंदर और मेहरबान बताते हैं कि हम व्यवहार में विविधता की अवधारणा को बेच रहे हैं। पंजाब में भूमिगत जल संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हैं और अंधाधुंध एनपीके (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम) उर्वरकों एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है। हम ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करके पानी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे उत्पाद के वॉलमार्ट, टाटा के खेत के स्टोर और फाइव स्टार होटले में पहुंचने से पहले जालंधर की एक एजेंसी हमारे उत्पादों का निरीक्षण करके इस बात का प्रमाण हमें प्रदान करती है कि इन उत्पादों में कीटनाशकों और उर्वरकों का सीमित मात्रा में उपयोग हुआ है।

अपने उत्पादन के जरिए ऊंची आमदनी ने इन किसानों को खेतों में हाड़-तोड़ मेहनत करने वाली पहचान से इतर श्री सूट पहनकर अपने उत्पाद सब्जियों को स्टोर्स और फाइव

स्टार होटलों में पहुंचाने वाले के रूप में ही पहचान नहीं दी है बल्कि इन्हें वैश्विक पहचान भी दिलाई है। देविंदर ने पिछले साल रूस का दौरा किया था जिसके बारे में वे बताते हैं कि वह मिर्च का एक बड़ा बाजार है। मेहरबान ने ब्रिटेन का दौरा कर लौकी के निर्यात की संभावनाएं टटोली। रूस में मिर्च 200 रुपये प्रति किलो बिकती है जबकि ब्रिटेन में लौकी की खुदरा मूल्य दो पाउंड प्रति किलो है। अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए दोनों बताते हैं कि उनकी योजना अपने फार्म में प्रेडिंग, पैकिंग और कूलिंग की सुविधा जुटाने की है ताकि सब्जियों की ताजगी को लंबे समय तक बचाए रखा जा सके। देविंदर कहते हैं कि इससे न केवल अपने उत्पाद के एक बड़े हिस्से को वे बर्बाद होने से बचा सकेंगे बल्कि दुनिया के बाजारों से भी जुड़ पाएंगे।

(साभार: इफकोलाइव.कॉम)

रूस में खेती करेगा भारत



भारत अब रूस में खाली पड़ी जमीन पर खेती कर अपनी खाद्यान्न जरूरत को पूरी करने पर विचार कर रहा है। इस बारे में दोनों देशों के बीच पहले से ही बात चल रही है। चीन पहले ही रूस में पट्टे पर जमीन लेकर अपनी आबादी के लिए अनाज और फल-सब्जियां उगा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसी तर्ज पर भारत भी कुछ वर्षों में रूस की जमीन पर खाद्यान्न पैदा करे।

हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत में कृषि एक अहम मुद्दा रहा है। बैठक में कृषि से जुड़े तमाम क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करने पर सहयोग देने के लिए एक समिति गठित की

गई है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कृषि और फार्मास्युटिकल्स दो ऐसे क्षेत्र हैं जो आने वाले दिनों में भारत व रूस के द्विपक्षीय रिश्तों को बिल्कुल नया आयाम देंगे। भारत व रूस के द्विपक्षीय रिश्ते अभी तक बहुत हद तक रक्षा व ऊर्जा तक ही सीमित हैं। दोनों देश अब दूसरे क्षेत्रों में विस्तार करना चाहते हैं। वैसे भी भारत अपनी रक्षा जरूरत के लिए अब दूसरे देशों पर रूस से भी ज्यादा निर्भर रहने लगा है। स्वराज और रोगोजिन के बीच हुई मुलाकात में इस संदर्भ में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में कदम उठाए जाएंगे।

भारत अन्य देशों में भी खाद्यान्न उत्पादन कर अपनी जरूरत पूरी करने पर योजना बना रहा है। दो वर्ष पहले जब भारत में दाल का संकट हुआ था तब भारत ने म्यांमार, मोजाम्बिक और नामीबिया में दलहन उपजाने पर वहां की सरकारों से बात की थी। खाद्य तेल का उत्पादन दूसरे देशों में करने के लिए भी भारत इच्छुक है। इसके लिए थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ चर्चा की जा रही है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि रूस के पास काफी खाली जमीन है और भविष्य में खाद्यान्न की भारी मांग को देखते हुए वहां खेती कर अनाज भारत लाने का तरीका एक बढ़िया नुस्खा हो सकता है।

रूस खुद चीन को साइबेरिया और पूर्वी सीमा के राज्यों में कृषि में निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहा है। रूस की जमीन कुछ खास तरह के कृषि उत्पादों के लिए काफी उपजाऊ है। भारत वहां खेती कर उत्पादों को घरेलू बाजार के लिए ला सकता है। यह काम चीन पहले से ही रूस की पूर्वी सीमा पर कर रहा है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत व चीन को आने वाले कुछ दशकों में अपनी जरूरत के कृषि उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों में उपजाना पड़ेगा। बढ़ती आबादी, जमीन की उर्वरा शक्ति में हो रहे क्षरण आदि की वजह से भारत के लिए भी अपनी घरेलू जमीन से पूरी आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा। इन दोनों देशों में बड़े पैमाने पर होने वाले औद्योगीकरण को भी एक कारण बताया गया था। दाल और खाद्य तेल उत्पादन में यह स्थिति अभी ही बन गई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 फीसद खाद्य तेल बाहर से आयात कर रहा है। दलहन भी बड़े पैमाने पर आयात किया जाता रहा है। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब भारत तिलहन-दलहन के अलावा अन्य अनाज के लिए भी विदेशी जमीन पर निर्भर हो जाए। ●



किसानों की आय दोगुनी करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करना है: राधा मोहन सिंह

25 से 27 फरवरी तक चले गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के समापन अवसर केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के काम की सराहना की और कहा कि इस विश्वविद्यालय को वर्ष 2016 में ब्रिक्स देशों के 200 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में जगह मिली है। इसी महीने एशिया के सर्वश्रेष्ठ 350 विश्वविद्यालयों में भी इसका नाम दर्ज हुआ है। यह देश का दूसरा एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जिसे यह गौरव प्राप्त हुआ है। कृषि अनुसंधान, शिक्षा, प्रसार में इस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण काम किए हैं।

श्री सिंह ने गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर परिसर में राष्ट्रीय बीज निगम के क्रियाशील बीज प्रोसेसिंग संयंत्र का लोकार्पण भी किया। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा पहली बार एक बीज प्रोसेसिंग संयंत्र तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय क्षेत्र में बीज उत्पादन में आ रही कठिनाइयां दूर हो सकेंगी। पर्वतीय क्षेत्र के किस्मों के बीजों का, मैदानी क्षेत्रों में उत्पादन व्यवसायिक रूप में सफल नहीं रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों से बीजों के मैदानी क्षेत्रों में प्रसंस्करण हेतु ढोकर लाने में यातायात

खर्च बढ़ जाता था, जिससे बीज महंगे हो जाते थे। इस प्लांट को अब पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा जिससे किसान अपने बीजों का वहीं विकास कर सकेंगे। इस प्रकार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की विकसित प्रजातियों के बीज उसी जलवायु में बनाए जाएंगे, जिससे न केवल पर्वतीय क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा बल्कि यहां की विलुप्त हो रही विशेष किस्म का संरक्षण भी हो सकेगा।

मंत्री महोदय ने कहा कि पहाड़ की कुछ फसलों का उद्भव व विकास जलवायु विशेष के कारण हुआ है। यहां पर औषधीय गुण वाले पौधे, फसलों की किस्में सदियों से उगाई जाती रही हैं। फसलों में रागी (मंडुआ), सावां (झगोरा) की विशेष प्रजाति उगाई जाती रही है जो अब विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि पहाड़ में विकसित विशेष गुणों वाली फसलों के विकास एवं संरक्षण पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं सरकार किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए सरकार ने बजट 2018-19 में कृषि एवं किसान कल्याण के विषयों को अभूतपूर्व प्राथमिकता देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजटीय आवंटन पिछले वर्ष यानि 2017-18 के 51,576 करोड़ से बढ़ाकर 2018-19 में 58,080 करोड़ कर

दिया है। सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वह उत्पादन केन्द्रित कार्यनीति से हटकर आय बढ़ाने वाली योजनाओं के समन्वयन एवं क्रियान्वयन को प्राथमिकता दे रही है।

इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुझाये गये 'बहु-आयामी सात सूत्रीय' कार्यनीति को अपनाने को प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें शामिल हैं-

- प्रति बूंद अधिक फसल के सिद्धांत पर पर्याप्त संसाधनों के साथ सिंचाई पर विशेष बल।
- प्रत्येक खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार गुणवत्ता वाले बीज एवं पोषक तत्वों का प्रावधान।
- कटाई के बाद फसल नुकसान को रोकने के लिए गोदामों और कोल्डचेन में बड़ा निवेश।
- खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार एवं सभी 585 केन्द्रों पर कमियों को दूर करने के लिए ई-प्लेटफार्म का क्रियान्वयन।
- जोखिम कम करने के लिए कम कीमत पर फसल बीमा योजना की शुरुआत।
- डेरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मेढ़ पर पेड़, बागवानी व मछली पालन जैसे संबद्ध कार्यकलापों को बढ़ावा देना।



GARHWAL AIRCON SERVICES PVT. LTD.

Preferred Dealer : Hitachi AC All Range

Sale, Services, Repair, Maintenance, Installation of Air Conditioner System,
W A/C, S A/C, Chillers & VRF (Set Free)

Head Office: K-13A, Khirki Extn. (Basement), Malviya Nagar, New Delhi-110017

Phone: 011-26671977, 26675127, Telefax: 011-26677219, Mob.: 9810320610

Site Office: 28-31, Vijay Complex Vakil Market, Vhakkarpur, Opp. Sahara Mall, Gurgaon, Haryana

Phone: 0124-6577704, Mob.: 9810397571, 9873562803

Shop No. 28-31, Chandila Market, Tagaon Road, Near Omaxe Height

CAPITAL TAXI SERVICES

Round the Clock
24 Hours



Ajay Sati

Mob: 9313455505, 8800595533

Jor Bagh Road, New Delhi-110003 Phone: 011-24655533, 24655505

E-mail: capitaltaxiservice@yahoo.co.in Website: capitaltaxiservice.com





संरक्षित कृषि यंत्रों का कृषि उत्पादन में योगदान

जितेन्द्र जोशी,
आशुलता नेताम, हेमलता

कृषि यांत्रिकीकरण का कृषि उत्पादकता से सकारात्मक संबंध प्राथमिक तौर पर कृषि प्रक्रियाओं की समयबद्धता एवं दूसरे गुणवत्तापूर्ण कार्य के कारण होता है। संरक्षित खेती के माध्यम से मिट्टी में कर्बनिक पदार्थों की वृद्धि होती है जिससे पौधों का जड़िय क्षेत्र एवं मिट्टी संरचना मजबूत बनती है। समय एवं श्रम की बचत के साथ उपयोग में लिए जाने वाले जल की मात्रा में कमी भी इस उन्नत तकनीकी को अपनाने हेतु प्रेरित करती है। चालन लागत में कमी एवं समय पर बुआई कार्य किये जाने के लिए संरक्षित कृषि तकनीकी ने कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जुताई कार्य को बुआई के साथ में एक ही बार में किये जाने से तेल की बचत एवं भूमि की उपरी सतह पर दबाव भी कम पड़ता है जिससे जड़िय क्षेत्र तक की मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचता है। धान के फसल की कटाई देर से होने की दशा में उपरोक्त तकनीक से निर्धारित समय पर बुआई कर किसान पैदावार में कमी होने की संभावना को दूर कर सकते हैं। हरियाणा, बिहार, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में

उपरोक्त तकनीक की सार्थकता सर्वविदित हैं। कई जगहों पर कंबाइन से काटी गेहूं फसलों में ट्रैक्टर चालित भूसा कंबाइन एवं स्ट्रा बेलर का उपयोग भी किसानों की बुआई पूर्व समस्याओं के हल के रूप में सामने आया है। कंबाइन से फसल कटाई उपरांत संरक्षित खेती के अधीन आने वाले नवीन कृषि यंत्रों जैसे जीरो टिल सीड ड्रिल, स्ट्रिप टिल सीड ड्रिल, रोटो टिल सीड ड्रिल, टिल प्लांट मशीन, हैप्पी सीडर का प्रचालन अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुआ है बुआई पूर्व मिट्टी पर भूसे या फसल के तिनकों से खेत को आच्छादित करने से खरपतवारों की स्वतः ही रोकथाम हो जाती है। अतः उपरोक्त तकनीक में खरपतवार नाशक रसायनों का उपयोग बढ़ने की बात निराधार है। मिट्टी में जड़ों के मिश्रित होकर खाद बनाने से कार्बन की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने में सहायक सिद्ध होती है। यह तकनीक जैव विविधता एवं कार्बन सांद्रणीकरण में वृद्धि करती है एवं अधिक मात्रा में खेत की सतह से भूमि के अंदर पानी का संचयन करने में सहायक होती है। संरक्षित कृषि में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टर चालित नवीन कृषि उपकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं -

ट्रैक्टर चालित कृषि उपकरण

1. **ट्रैक्टर चालित जीरो टिल सीड ड्रिल** : यह 9 एवं 11 कतारी मशीन है जिसकी कार्यक्षमता 0.31 हेक्टेयर प्रति घंटा है। इस मशीन में इनवर्टेड-टी प्रकार के फरो ओपनर लगे होते हैं। इस एक मशीन के उपयोग से प्रति वर्ष 45 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की जा सकती है। पारंपरिक ट्रैक्टर चालित बुआई मशीन की तुलना में इस मशीन से 1,500 से 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की बचत हो सकती है। किसानों के बीच इस समय 25,000 मशीन कार्यरत हैं जिनसे लगभग 225 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ हो रहा है। इस मशीन को लगभग 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उपयोग में लाया जा रहा है। देशभर में 60 कृषि निर्माता कंपनियां इसके निरंतर निर्माण में लगी हैं। पारंपरिक बुआई की तुलना में यह मशीन श्रम एवं समय में 50 से 60 प्रतिशत एवं प्रचालन लागत में 40 प्रतिशत तक कमी करती है। इस मशीन के उपयोग से 10 से 15 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत भी होती है। मशीन की कीमत 32,000 रुपये एवं प्रचालन लागत 1,400 रुपये प्रति हेक्टेयर है।

2. **ट्रैक्टर चालित स्ट्रिप टिल ड्रिल** : यह मशीन संरक्षित कृषि के अंतर्गत 75 मिमी. की पट्टी प्रति स्ट्रिप में जुताई के साथ बुआई संपन्न करती है। इसकी क्षमता 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा एवं प्रचालन लागत 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। एक मशीन से प्रतिवर्ष 30 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई संभव है जिससे कि 42,000 रुपये प्रतिवर्ष लाभ अर्जित किया जा सकता है। वर्तमान में ऐसी 500 मशीनें देशभर में कार्य कर रही हैं जिनसे 210 लाख रुपये का वार्षिक लाभ हो रहा है। इस मशीन की कीमत 83,000 रुपये है।

3. **ट्रैक्टर चालित रोटो टिल ड्रिल** : यह मशीन जुताई एवं बुआई के कार्य को एक बार में संपन्न कर सकती है। मशीन की कीमत 1.07 लाख रुपये है। एक मशीन से 40 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रति वर्ष बुआई की जा सकती है। मशीन की कार्यक्षमता 0.30 हेक्टेयर प्रति घंटा है एवं प्रचालन लागत 1800 रुपये प्रति हेक्टेयर आती है। इसके उपयोग में 40 से 50 प्रतिशत प्रचालन लागत में कमी आती है।

4. **ट्रैक्टर चालित टिल प्लांट मशीन** : यह मशीन जुताई द्वारा खेत तैयार करने एवं

बुआई कार्य एक साथ संपन्न कर सकती है। इस मशीन में जुताई के लिए 7 स्वीप युक्त फ्रेम पर बीज खाद डालने वाली इकाई संबंध करके निर्मित किया गया है जिसमें नुकीले शू वाले फरो ओपनर प्रयुक्त होते हैं। मशीन की कार्यक्षमता 0.60 हेक्टेयर प्रति घंटा है। यह मशीन पारंपरिक बुआई की तुलना में 85 प्रतिशत समय की बचत करती है एवं प्रचालन लागत में भी 83 प्रतिशत की कमी होती है।

5. पावर टिलर चालित टिल प्लांट मशीन :

यह मशीन 10 से 12 एच.पी. के पावर टिलर के साथ संबंध रहती है जिससे एक बार में ही खेत की जुताई एवं बीज एवं खाद की उपयुक्त मात्रा उचित गहराई पर डाली जा सकती है। मशीन की कार्यक्षमता 0.1 हेक्टेयर प्रति घंटा है एवं कार्य दक्षता 60 से 65 प्रतिशत है। इसके उपयोग में 9-12 श्रम-घंटे प्रति हेक्टेयर लगते हैं। मशीन की कीमत 10,500 रुपये एवं प्रचालन लागत 825 रुपये प्रति हेक्टेयर है। इससे गेहूं, चना और सोयाबीन की बुआई मध्यम एवं भारी मिट्टी में की जा सकती है।

6. ट्रैक्टर चालित बेड प्लांट : यह मशीन चौड़ी बेड के साथ में बुआई कार्य भी संपन्न करती है। इस मशीन के उपयोग से गेहूं, चना, मटर, राया, ज्वार एवं मूंग की बुआई सफलतापूर्वक की जा सकती है। मशीन की कीमत 62,000 रुपये है। इसकी कार्यक्षमता 0.2 हेक्टेयर प्रति घंटा है। इसके उपयोग से पारंपरिक समतल बुआई की तुलना में बीज एवं खाद में 15 प्रतिशत तथा सिंचाई जल में 25 प्रतिशत की बचत संभव है। एक मशीन से वर्ष भर में 20 हे. क्षेत्र में बुआई संभव



है जिससे कि 90,000 रुपये प्रति वर्ष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देशभर में ऐसी 500 मशीनें काम कर रही हैं।

7. सकरे पहिये वाले ट्रैक्टर से बेड बनाने, बुआई, खरपतवार निराई, दवा छिड़काव एवं कटाई यंत्र : भारत में परंपरागत ट्रैक्टर के पहिये खेत की जुताई ठीक से करने के लिए काफी चौड़े बने होते हैं। लेकिन फसल की बुआई के बाद दो कतारों के मध्य कम अंतर होने पर यह चौड़ाई एक समस्या बन जाती है। चौड़े पहिये वाले ट्रैक्टर से फसल में निराई एवं दवा छिड़काव करने पर अधिक मात्रा में पौधे ट्रैक्टर के पहिये के नीचे आ जाते हैं तथा ये खेत की मिट्टी को अधिक दबाते हैं। ऊंचे और समतल मिट्टी के बेड पर ट्रैक्टर से खेती करने के लिए सकरे पहिये की आवश्यकता है जिससे निराई और रसायनों का खड़ी फसल पर छिड़काव पौधों के नुकसान के बिना किया जा सके।

सक्रे पहिये के 35 हार्स पावर वाले ट्रैक्टर को खेती करने में आसानी को देखते हुये उपयोग में लाया गया तथा ट्रैक्टर के

सामने चलने वाले फसल कटाई यंत्रों के लिए एव पावर टेक ऑफ यूनिट लगायी गई। सकरे पहिये के कारण कतार में बोये गये पौधों के बीच ट्रैक्टर चलाने के लिए अधिक जगह मिलती है। जिससे सोयाबीन, मूंगफली आदि फसलों में निराई एवं दवा छिड़काव आसानी से किया जा सके। ऊंचे और समतल मिट्टी के बेड ट्रैक्टर से बनाने के लिए यंत्र की क्षमता 0.3 हेक्टेयर प्रति घंटा तथा गति 2.3 कि.मी. प्रति घंटा थी। इससे ऊपर से 1200 मिमी. चौड़े और नीचे से 1500 मिमी. चौड़े मिट्टी के बेड बनाये गये। इसकी औसत ऊंचाई 130 मिमी. थी। इन पर 350 मिमी. की दूरी पर चार कतारों में सोयाबीन बोयी गई। पांच कतारी निराई यंत्र से सोयाबीन में निराई की गई। 225 मिमी. चौड़ी पांच स्वीप को 35 मिमी. की दूरी पर लगाकर सोयाबीन में निराई की गई। यंत्र की क्षमता 0.28 हेक्टेयर/घंटा तथा गति 2.41 किमी./घंटा थी। देखा गया कि पौधों को 2 प्रतिशत नुकसान हुआ।

सोयाबीन और मटर के पौधों पर रसायनों का छिड़काव हाइड्रोलिक स्प्रेयर से किया गया। रसायनों का छिड़काव 8.5 मी. के घेरे में 343 किलो पास्कल के दबाव पर 6.37 लीटर प्रति मिनट की दर से किया गया। यंत्र की क्षमता 1.73 हेक्टेयर प्रति घंटा तथा गति 2.52 किमी. प्रति घंटा थी। यंत्र की दक्षता 82 प्रतिशत थी। ट्रैक्टर के आगे लगने वाले 2200 मिमी. चौड़े फसल कटाई यंत्र (रीपर) से गेहूं की कटाई 2.48 किमी. प्रति घंटा की गति से की गई। कटर बार 700 स्टोक्स प्रति मिनट की गति से चालित थे। इस यंत्र की क्षमता 0.28 हेक्टेयर प्रति घंटा तथा दक्षता 68 प्रतिशत थी।

—लेखकगण इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर
में पीएच.डी. शोधकर्ता हैं





सूरजमुखी की व्यावहारिक खेती

सूरजमुखी की फसल को सभी मौसमों की फसल की संज्ञा दी जाती है। पुष्पन अवस्था में यह फसल खेती के अधीन सारे क्षेत्र को दर्शनीय एवं आकर्षक बना देती है एवं परिपक्व होने पर उच्च कोटि का खाद्य तेल प्रदान करती है।

■ डॉ. गंगाशरण सैनी

तिलहनी फसलों में सूरजमुखी का प्रमुख स्थान है। इसकी व्यवसायिक खेती का श्रीगणेश जुलाई 1969 में गो. व. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुआ था। बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रेरणा से सन् 1960-70 के रबी मौसम में अखिल भारतीय स्तर पर इस फसल का परीक्षण प्रारंभ किया गया। इस फसल को सभी मौसमों की फसल की संज्ञा दी जाती है। पुष्पन अवस्था में यह फसल खेती के अधीन सारे क्षेत्र को दर्शनीय एवं आकर्षक बना देती है एवं परिपक्व होने पर यह उच्च कोटि का खाद्य तेल प्रदान करती है।

सूरजमुखी से प्राप्त खाद्य तेल उत्तम कोटि का होता है, जो हल्के पीले वर्ण का होता है और स्वाद में अति उत्तम होता है। इसमें टिकाऊपन भी अधिक होता है और बहु-असंतृप्त वसा अम्ल विशेष रूप

से लिनोलिक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यह खाद्य तेलों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूरजमुखी का तेल अम्ल रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को रोकने के अतिरिक्त उस पर अपचायक प्रभाव भी डालता है। यही प्रमुख कारण है कि इसके तेल का उपयोग दिन-प्रतिदिन तीव्र गति से बढ़ रहा है।

सूरजमुखी का मूल स्थान दक्षिणी अमेरिका व मैक्सिको है और वहां से 16वीं शताब्दी में यह स्पेन में पहुंची। इसके तेल में ओलिक एसिड पाया जाता है, जिसका उपयोग कन्फेक्शनरी में किया जाता है। सनफ्लावर मील में प्रोटीन आदि विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पशुचारे का उत्तम स्रोत है। सूरजमुखी के बीजों का छिलका भी पशु आहार के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

रसियन फेडरेशन सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद अर्जेन्टीना,

यूक्रेन, यू.एस.ए., रोमानिया और स्पेन का नंबर आता है। भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा इसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में उगाया जाता है।

जलवायु

सूरजमुखी की खेती कृषि जलवायु की परिस्थितियों के अनुकूल होती है। सूरजमुखी का पौधा तापमान के प्रति संवेदनशील होता है। इसके जीवन चक्रम जैसे अंकुरण, निर्गमन, वृद्धि, विकास, परिपक्वता आदि और तेल की गुणवत्ता व मात्रा आदि पर तापमान के कारण फसल लगभग 130 दिन में तैयार होती है, जबकि खरीफ मौसम में उच्च तापमान होने के कारण मात्र 80 दिन लगते हैं। यद्यपि इसकी खेती किसी भी जलवायु में आसानी से की जा सकती है।

भूमि

सूरजमुखी को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। सूरजमुखी के पौधे सिंचित रेतीली मृदाओं से लेकर उच्च नमी बनाये रखने वाली मटियार मृदाओं तक और हल्की अम्लीय से लेकर 8.5 पी.एच. मान वाली मृदाओं तक विविध प्रकार की मृदाओं में अच्छे पनपते हैं। अच्छे परिणाम प्राप्त करने हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि बोआई हेतु गहरी, उर्वर एवं उदासीन अभिक्रिया वाली मृदाओं को प्राथमिकता दी जाए। बरसात में जल निकास की समुचित व्यवस्थाएं अनिवार्य हों। सूरजमुखी अस्थायी सूखे की दशाओं का मुकाबला कर सकती है इसलिए इसे बारानी क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक की काली कपासीय मृदाओं में सूरजमुखी, मूंगफली से अच्छी उपज देती है।

खेत की तैयारी

हल्की रेतीली मृदाओं में 1 या 2 बार 25-30 से.मी. तक जुताई करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के उपरान्त पाटा लगाना चाहिए। जबकि मध्यम एवं भारी संरचना वाली मृदाओं में 1 या 2 बार जुताई करनी चाहिए। जुताई के उपरान्त समतलीकरण करना चाहिए। समतलीकरण से सिंचाई का पानी पौधों को बराबर मात्रा में पहुंचता है।

उन्नत किस्में

- **के.बी.एस.एच.-41 (संकर)** : यह किस्म 80-90 दिन में तैयार हो जाती है, जो असिंचित एवं सिंचित परिस्थितियों में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। इसे खरीफ एवं रबी दोनों मौसमों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इस किस्म पर कीट एवं रोगों का प्रकोप कम होता है। इसके बीजों में 39-41 प्रतिशत तक तेल पाया जाता है। बारानी व सिंचित क्षेत्रों में क्रमशः 13-17 व 25-30 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज देती है।
- **डी.आर.एल.एच.-1 (संकर)** : यह किस्म 90-98 दिन में तैयार हो जाती है। सिंचित व असिंचित दशा में जायद व रबी मौसम में उगाने हेतु उपयुक्त किस्म है। इसके दानों में 42-44 प्रतिशत तेल पाया जाता है। यह किस्म सम्पूर्ण भारत में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। प्रति हैक्टेयर 13 से 16 क्विंटल उपज दे देती है।
- **के.बी.एस.एच.-531 (संकर)** : यह किस्म 95-100 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। यह गिरने के प्रति सहनशील किस्म है। यह किस्म चूर्णी फफूंदी के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। इसके दानों में 42-44 प्रतिशत तेल पाया जाता है। प्रति हैक्टेयर 17 से 27 क्विंटल उपज देती है।
- **के.बी.एस.एच.-44 (संकर)** : यह 88-92 दिन में तैयार होने वाली किस्म है।

यह खरीफ व रबी मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। यह कीट व रोगों की प्रतिरोधी किस्म है। इसके दानों में 36-38 प्रतिशत तेल पाया जाता है। यह संपूर्ण भारत में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। प्रति हैक्टेयर 14 से 16 क्विंटल उपज देती है।

● **डी.आर.एस.एफ.-108 (संकुल)** : यह मध्यम अवधि (90-95) पकने वाली किस्म है। इसके दानों में 36-39 प्रतिशत तेल पाया जाता है।

खाद एवं उर्वरक

सूरजमुखी उत्पादन हेतु मध्यम कोटि की उर्वर मृदाएं अनुकूल होती हैं। इसके पौधे भूमि से पोटेशियम की भारी मात्राएं ग्रहण करते हैं, परन्तु उनकी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस संबंधी आवश्यकताएं साधारण होती हैं। इसके परिपक्व बीजों में पौधों द्वारा अवशोषित फास्फोरिक एसिड का 3/4 भाग होता है। मृदा में फास्फोरस उपलब्ध होने पर जड़ों का विकास भलीभांति हो जाता है। पोटेशियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों के पीले पड़ने के रूप में प्रकट होते हैं, जिसके बाद सम्पूर्ण पत्ती में जले जैसे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। ये धब्बे सर्वप्रथम मुख्य शिरा के साथ और बाद में अन्य शिराओं के साथ-साथ फैलते हैं। पोटेशियम की अधिक कमी से बीज खाली रह जाते हैं। उपज में

NEW INDIA ASSOCIATES

- Life Insurance/LIC Credit Card
- Car/Home Insurance
- Mediclaim

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

RELIANCE
General Insurance
RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY

Narendra Singh Bisht
48, Hasanpur, I.P. Extension, Delhi-110092
Phone: 011-49404552, 22240184
Mobile: 9810369331, 9717494411
E-mail: anjal2006@gmail.com



मिसाल-बेमिसाल

यह कोई आम महिला नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके बस्तर टाड़गर महेन्द्र कर्मा की पत्नी और दत्तेवाड़ा से कांग्रेस विधायक देवती कर्मा हैं। विधायक देवती कर्मा जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ कृषक और घरेलू महिला हैं। जन समस्या को सड़क से सदन तक पहुंचाने के साथ ही वह खेती-किसानी में भी बखूबी जुटी रहती हैं। छत्तीसगढ़ के झीरम कांड में महेन्द्र कर्मा की शहादत के बाद पूरे परिवार को जेड प्लस सुरक्षा मिली है। लिहाजा दत्तेवाड़ा विधायक देवती कर्मा के साथ हमेशा जवानों की मौजूदगी रहती है।

भारी कमी हो जाती है। संपूर्ण विश्व में किये गये उर्वरता प्रबंध संबंधी परीक्षणों से पता चला है कि सूरजमुखी का उत्पादन 40-50 किलोग्राम नाइट्रोजन की सामान्य मात्रा पर अच्छा होता है। गो. ब. पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में किये गये परीक्षणों के आधार पर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन व 60 किलोग्राम फास्फोरस की संस्तुति की गई है। कुल नाइट्रोजन का 1/3 भाग फूल खिलने के समय देना चाहिए।

बोआई

सूरजमुखी की फसल दिन की लंबाई से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए इसकी किसी भी समय इसकी बोआई की जा सकती है। वैसे सूरजमुखी की बोआई का उचित समय का निर्धारण किसी विशेष फसल-चक्र के लिए उपलब्ध भूमि के आधार पर किया जाता है।

1. बसंतकालीन फसल के लिए 15 जनवरी से 10 फरवरी तक
2. बारानी खेती वाले क्षेत्रों के लिए मानसून के शुरू होने पर
3. गन्ने वाले खेतों में गन्ने की कटाई के बाद 15 नवंबर से 3 दिसंबर तक

बीज दर

सूरजमुखी के बीज भार में हल्के (55 से 70 ग्राम प्रति 1000 बीज) होते हैं। इसलिए 8-10 किलोग्राम बीज प्रति हैक्टेयर पर्याप्त होते हैं, क्योंकि इस दर से बोआई करने पर अंकुरण अच्छा न होने पर भी 60-80 हजार पौधे प्रति हैक्टेयर उग आते हैं।

विधि

शीतोष्ण देशों में जहां यांत्रिक खेती की जाती है वहां पंक्ति से पंक्ति के मध्य की दूरी 50-60 सेमी की अपेक्षा 80 सेमी. रखी जाती है। पंतनगर में किये गये परीक्षणों से भी पता चला है कि 80 सेमी. दूरी अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त रहती है।

बीज की गहराई

सूरजमुखी के बीजों का अंकुरण धान्य फसलों की अपेक्षा अधिक देर से होता है, क्योंकि सूरजमुखी के बीजों का छिलका मोटा

होता है, जिसके कारण जल का अवशोषण धीमी गति से होता है और अंकुरण भी उपरिभूमिक होता है। इसके अतिरिक्त मृदा की पपड़ी अंकुरण की गति को और अधिक धीमी कर सकती है। इसलिए रोपण को कम गहराई पर करना अधिक अच्छा समझा जाता है। पंतनगर में किये परीक्षणों में 2-4 से.मी. की गहराई को अधिक अच्छा माना गया है।

बीजोपचार

बीज को बोने से पूर्व 0.3 प्रतिशत कैप्टान से उपचारित कर लेना चाहिए, ताकि फसल का फफूंदीजनक रोगों से बचाव हो सके।

सिंचाई एवं जल निकास

यद्यपि इस फसल को बारानी क्षेत्रों में उगाया जा सकता है फिर भी सिंचाई का फसल के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हल्की संरचना वाली मृदाओं में 8-10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, जबकि भारी संरचना वाली मृदाओं में 15-25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए।

सूरजमुखी की फसल तीन क्रांतिक अवस्थाओं से गुजरती है, जिनमें सिंचाई निम्नानुसार करनी चाहिए:

- कलिका बनने की अवस्था में: इस अवस्था में बीज बोने के 35-40 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए।
- फूल खिलने की अवस्था में: इस अवस्था में बीज बोने के 55-65 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए।
- बीज भरने की अवस्था में: इस अवस्था में बीज बोने के 65-80 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए।

शुष्क मौसम में जल-निकास की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि खरीफ की फसल में जल निकास की ओर पर्याप्त ध्यान देना अनिवार्य है। जल एक जगह एकत्रित होने पर पौधों को नुकसान हो सकता है।

पौध संरक्षण और खरपतवार

सूरजमुखी का पौधा प्रथम 4-6 सप्ताहों में धीमी गति से वृद्धि करता है। अतः इस अवधि में 2 बार खरपतवार निकालना अच्छा रहता है। पहली निराई बोआई के 24-30

फार्म - 8

(नियम 8 देखिए)

- | | | |
|---|---|--|
| 1. नाम | : | कृषि चौपाल |
| 2. प्रकाशन-स्थान | : | दिल्ली |
| 3. प्रकाशन-अवधि | : | मासिक |
| 4. मुद्रक का नाम | : | महेन्द्र सिंह बोरा |
| क्या भारत के नागरिक हैं? | : | हां |
| यदि विदेशी हैं तो मूल देश का नाम | : | नहीं |
| पता | : | सी-355, तृतीय तल, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 |
| 5. प्रकाशक का नाम | : | महेन्द्र सिंह बोरा |
| क्या भारत के नागरिक हैं? | : | हां |
| यदि विदेशी हैं तो मूल देश का नाम | : | नहीं |
| पता | : | सी-355, तृतीय तल, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 |
| 6. संपादक का नाम | : | महेन्द्र सिंह बोरा |
| क्या भारत के नागरिक हैं? | : | हां |
| यदि विदेशी हैं तो मूल देश का नाम | : | नहीं |
| पता | : | सी-355, तृतीय तल, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 |
| 7. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी हों या जिनका हिस्सा हो | : | महेन्द्र सिंह बोरा
सी-355, तृतीय तल, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 |

मैं महेन्द्र सिंह बोरा एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक: 01.03.2018

महेन्द्र सिंह बोरा
(प्रकाशक एवं मुद्रक)

दिन बाद और दूसरी सिंचाई के साथ मिट्टी चढ़ाने का काम कर देना चाहिए, ताकि पौधों की जड़ें उखड़ने न पाएं और फसल न गिरे। एलाक्लोर, पेन्डीमिथेलीन या फ्लूकोलोरालीन की 1.5 किलो/मात्रा को 600 लीटर पानी में घोल कर शाम को छिड़काव कर देना चाहिए। ध्यान रहे कि छिड़काव के समय भूमि में पर्याप्त नमी हो।

रोग नियंत्रण

आल्टरनेरिया पत्ती झुलसा: यह रोग आल्टरनेरिया हेलिएंथी नामक फफूंदी के कारण होता है। यह रोग केवल खरीफ की फसल में उन क्षेत्रों में उग्र रूप धारण कर लेता है जहां वर्षा 80 सेमी से अधिक होती है। इस रोग में गहरे भूरे रंग से लेकर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये धब्बे बाद में संकेन्द्री हो जाते हैं। सामान्यतया प्रत्येक धब्बे के चारों ओर एक हरिमाहीन क्षेत्र पात्रा जाता है। रोग की उग्र अवस्था में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरी पत्ती सूख जाती है। रोग पत्तियों के डंठलों, तनों, डिस्क के पृष्ठ भाग में भी फैल सकता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु निम्न उपाय करने चाहिए -

- केवल रोगमुक्त बीजों को ही बोएं।
- उचित फसल चक्र अपनाएं।
- बीज को कैप्टान थीरम (3 ग्राम/किलो बीज) से उपचारित करके बोएं।

डाउनी मिलड्यू: यह प्लाज्मोपारा हल्सीडी

नामक फफूंदी के कारण होता है। रोगी पौधे बौने, सीधे खड़े, पीले-हरे होते हैं। संक्रमित पत्तियां कठोर हो जाती हैं एवं गांठों के बीच की लंबाई कम हो जाने के कारण रोगी पौधों की पत्तियां स्थूल या मोटी एवं भंगुर हो जाती हैं। इस रोग के नियंत्रण हेतु एलएसएच-1 और एलएसएच-3 संकर किस्में ही उगाएं। जल निकास की उचित व्यवस्था करें। उचित फसल चक्र अपनाएं। रोगी पौधों को सावधानी से उखाड़ कर जला दें। संक्रमित फसल पर डायथेन एम-45 के 2.5 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें।

कीट नियंत्रण

कटुआ कीट (एग्रोटिस प्रजाति): इसका पौधे की प्रारंभिक अवस्था में प्रकोप होता है। यह मटमैले रंग का लार्वा होता है। दिन के समय यह मिट्टी में छिपा रहता है और रात को निकलकर छोटे पौधों की जड़ को काट देता है, जिसके कारण उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कीट की रोकथाम के लिए निम्न उपाय करके चाहिए:

- बोआई मेड़ों पर करनी चाहिए।
- कीट ग्रसित फसल पर क्लोरी पाइरीफास 20 ईसी 3.75 लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ डालें।

सफेद मक्खी (बेमिसिया टबा सी): इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ पत्तियों का रस चूसते हैं। यह कीट एक प्रकार का मधु पौधों पर छोड़ता है जो 'शूटी मोल्ड' को

अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कीट की रोकथाम हेतु 0.03 प्रतिशत डाइमथोएट घोल का छिड़काव करना चाहिए।

कटाई एवं गहाई

सूरजमुखी की कटाई सही समय पर करना आवश्यक है, अन्यथा फसल कम हो सकती है। बीजों में तेल एवं प्रोटीन की मात्रा प्रफूलन के समय पूर्ण पाई जाती है। इस अवस्था में पौधे हरे होते हैं और मुंडक के सूखने से पूर्व ही बीज परिपक्व हो जाते हैं। अतः जब पुष्प आधार की पिछली सतह पीली हो जाती है, तो उस समय फसल को काटना उपयुक्त होता है।

फसल की गहाई करने से पूर्व फूलों को भली भांति सुखा लिया जाता है। लगभग एक सप्ताह तक सुखाने के बाद बीजों को डण्डों से पीटकर अलग कर लिया जाता है। अधिक क्षेत्र में उगायी जाने वाली फसल की गहाई थ्रेशर द्वारा की जा जाती है।

उपज

सूरजमुखी की फसल की उपज कई बातों पर निर्भर करती है जिनमें मृदा की उर्वरा शक्ति, बोआई की विधि, उगायी जाने वाली किस्म और फसल की देखभाल प्रमुख हैं। यदि सूरजमुखी को उपरोक्त वर्णित विधि से उगाया जाए तो 20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज मिल जाती है। ●



'कृषि चौपाल' पत्रिका डाक से मंगाने के लिए सदस्यता फॉर्म

- एक वर्ष (12 अंक) : रु. 240
- दो वर्ष (24 अंक) : रु. 450
- पांच वर्ष (60 अंक) : रु. 1100

सदस्य का नाम

डाक का पता

राज्य पिन कोड

फोन/मोबाइल ई-मेल

चेक/डिमांड ड्राफ्ट संख्या रुपये बैंक व ब्रांच का नाम

दिनांक हस्ताक्षर

-: कृपया ध्यान दें :-

पत्रिका भारतीय डाक विभाग की पोस्टल सेवा से भेजी जाएगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट 'KRISHI CHAUPAL' के नाम देय होगा। उसके पीछे अपना नाम, पता एवं फोन नंबर लिखकर नीचे दिये गये पते पर भेजें:-

कृषि चौपाल, सी-355, तृतीय तल, गली नं.-9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092, फोन: +91-991040-6059



मंडियों ने दगा दिया

■ जनकवि बल्ली सिंह चीमा

कभी धान को कभी गेहूं को, तेरी मंडियों ने दगा दिया।
मेरी खेतियों से तुझे बैर है, तेरी नीतियों ने बता दिया।

मैं किसान हूँ मेरा हाल क्या, मैं तो आसमां की दया पे हूँ।
कभी मौसमों ने हंसा दिया, कभी मौसमों ने रुला दिया।

ये कहानियां, ये लफ्फाजियां, तेरे मुंह से मुझको जंची नहीं।
मेरे गांव में ये रिवाज है, कहा जो भी करके दिखा दिया।

मेरी जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तू ही धूप है तू ही छांव है।
किसी शाम तूने रुला दिया, किसी शाम तूने हंसा दिया।

मैं गिरा तो गिर के उठा भी हूँ, यही फ़ख है कि झुका नहीं।
वो मशाल भी क्या मशाल है, जिसे आधियों ने बुझा दिया।

घाघ की कहावतें

गहिर न जोतै बोवै धान। सो घर कोठिला भरै किसान।।
गहरा न जोतकर धान बोने से उसकी पैदावार खूब होती है।

रोहिनी बरसै मृग तपै, कुछ कुछ अद्रा जाय।

कहै घाघ सुने घाघिनी, स्वान भात नहीं खाय।।

यदि रोहिणी बरसे, मृगशिरा तपै और आर्द्रा में साधारण वर्षा हो जाए तो धान की पैदावार इतनी अच्छी होगी कि कुत्ते भी भात खाने से ऊब जाएंगे और नहीं खाएंगे।

आसाढ़ी पूनो दिना, गाज बीजू बरसंत।

नासे लच्छन काल का, आनंद मानो सत।।

आषाढ़ की पूणिमा को यदि बादल गरजे, बिजली चमके और पानी बरसे तो वह वर्ष बहुत सुखद बीतेगा।

सर्व तपै जो रोहिनी, सर्व तपै जो मूर। परिवा तपै जो जेठ की, उपजै सातो तूर।।

यदि रोहिणी भर तपे और मूल भी पूरा तपे तथा जेठ की प्रतिपदा तपे तो सातों प्रकार के अन्न पैदा होंगे।

आद्रा में जौ बोवै साठी। दुःखै मारि निकारै लाठी।।

जो किसान आद्रा में धान बोता है वह दुःख को लाठी मारकर भगा देता है।

होशियार किसान

गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन उसकी बीवी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वह उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वह मक्खन गोल पेड़ों की शकल में बना था और हर पेड़े का वजन एक किलो था। शहर में किसान ने वह मक्खन हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया। बदले में दुकानदार से चायपत्ती, चीनी, तेल, साबुन वगैरह खरीदकर वापस अपने गांव को रवाना हो गया।

किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रिज में रखना शुरू किया। उसे खयाल आया के क्यूं ना एक पेड़े का वजन किया जाए। वजन करने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरत से उसने सारे पेड़े तोल डाले मगर किसान के लाये सभी पेड़े 900-900 ग्राम के ही निकले।

अगले हफ्ते किसान मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज पर पहुंचा, दुकानदार चिल्लाकर बोला- 'दफा हो जा यहां से, बेईमान कहीं का। बेईमान और धोखेबाज आदमी से कारोबार करना मुझे गवारा नहीं। 900 ग्राम मक्खन को पूरा एक किलो बताकर बेचने वाले की मैं शकल भी देखना पसंद नहीं करता...।'

किसान ने बड़ी विनम्रता से दुकानदार को जवाब दिया- 'मेरे भाई, हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं। माल तोलने के लिए बाट (वजन) खरीदने की हैसियत ही कहां है हमारी? आपसे जो एक किलो चीनी लेकर जाता हूँ उसी को तराजू के एक पलड़े पर रखकर दूसरे पलड़े पर उतने ही वजन का मक्खन तोलकर ले आता हूँ।'

यह सुनकर दुकानदार को सांप सूंघ गया। ●

कहर

पकी फसल पर असमय बरसात और ओलों के कहर ने किसानों के पेट और कमर पर जो लात मारी थी, उसी का सर्वे चल रहा था। कौन किस हद तक घायल है उसी हिसाब से मुआवजा मिलना था। सो, दो सरकारी मुलाजिम एक पुरवा से दूसरे पुरवा जा-जाकर कागज रंग रहे थे।

'भाग यहां से सोले, यहां आया तो तेरी खैर नहीं। हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तेरा मन नहीं भरा मेरे बाल-बच्चे खाकर? और कितनों को खायेगा? आ... ले, खा ले... सबको खाजा... आज, आ के दिखा... तुझे अभी मजा चखाता हूँ' कह कर वो अंधाधुंध पत्थर मारने लगा। उसकी विक्षिप्त-सी हालत देख दोनों सर्वेकर्ता दहशत में आ गये। उसमें से एक ने साथ खड़े ग्रामीण से पूछा-

'अरे भैया! इसे क्या हुआ? पागल है क्या?'

'अरे अब क्या बतायें हजूर! अच्छा-खासा मेहनती किसान था। पिछले साल इन्हीं दिनों ओलों ने इसका सब कुछ बरबाद कर दिया। लागत भी नहीं निकाल पाया बेचारा! ऊपर से साहूकार के तकाजे। सो खा लिया परिवार सहित जहर, कोई नहीं बचा! बस इसी की नहीं आई थी... सो बच गया, लेकिन बच्चों की लाशें देखकर दिमाग ठिकाने नहीं रहा।'

'ओहो... बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये पत्थर किसे मार रहा है?'

'उन्हें' असमय घिर रहे काले बादलों की ओर इशारा करते हुये वो ग्रामीण बोला।

■ राहिला

एक बार भुगतान कीजिए, हर दिन जिएं!



ज़िंदगी का मज़ा लेना शुरू करें आज से.



एकल प्रीमियम नॉन-लिंक्ड,
लाभ-रहित, तात्कालिक वार्षिकी प्लान
UIN-512N234V06 Plan No.: 189

- प्लान: एकल प्रीमियम तात्कालिक वार्षिकी प्लान
- आयु योग्यता:
(ए) प्रवेश के समय न्यूनतम आयु: पिछले जन्मदिन को 30 वर्ष.
(बी) प्रवेश के समय अधिकतम आयु: वार्षिक वृत्ति विकल्प एफ – खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन के लिए वार्षिक वृत्ति के लिए पिछले जन्मदिन को 100 वर्ष. वार्षिक वृत्ति विकल्प एफ – खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन के लिए वार्षिक वृत्ति के अलावा अन्य सभी वार्षिक वृत्ति विकल्पों के लिए पिछले जन्मदिन को 85 वर्ष।
- विविध विकल्प: 10 वार्षिकी विकल्पों में से कोई भी चुन सकते हैं।
- सुविधाजनक वार्षिकी भुगतान: मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिकी माध्यम उपलब्ध

उदाहरण :

आयु : 50, वार्षिकी भुगतान का माध्यम – वार्षिक

खरीदी कीमत*	विकल्प A	विकल्प F	विकल्प J
50 लाख	3,95,250	3,33,750	3,31,250
1 करोड़	7,90,500	6,67,500	6,62,500
2 करोड़	15,81,000	13,35,000	13,25,000

*विनियमानुसार टैक्स लागू

विकल्प A : जीवनभर वार्षिकी

विकल्प F : जीवनभर वार्षिकी का भुगतान, खरीद मूल्य की वापसी के साथ

विकल्प J : अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ वार्षिक वृत्तिधारी की मृत्यु पर जीवन-साथी को जीवन के लिए वार्षिक वृत्ति के 100 प्रतिशत का प्रावधान।

अधिक जानकारी के लिए, अपने एजेंट/ नजदीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या एसएमएस करें अपने शहर का नाम 56767474 पर या विजिट करें www.licindia.in पर.

Follow us : LIC India Forever

IRDAI Regn No.: 512

भ्रामक फोन कॉलस तथा फर्जी/धोखाधड़ी वाले ऑफर्स से सावधान आईआरडीएआई सर्वसाधारण को सूचित करता है: • आईआरडीएआई या इसके अधिकारी, बीमा विक्रय या वित्तीय उत्पाद अथवा प्रीमियम निवेश संबंधी गतिविधियों से संबंध नहीं रखते. • आईआरडीएआई किसी प्रकार के बोनस की घोषणा नहीं करता. ऐसे फोन आने पर कॉल विवरण तथा फोन नंबर की रिपोर्ट तुरंत पुलिस में दर्ज करवायें.

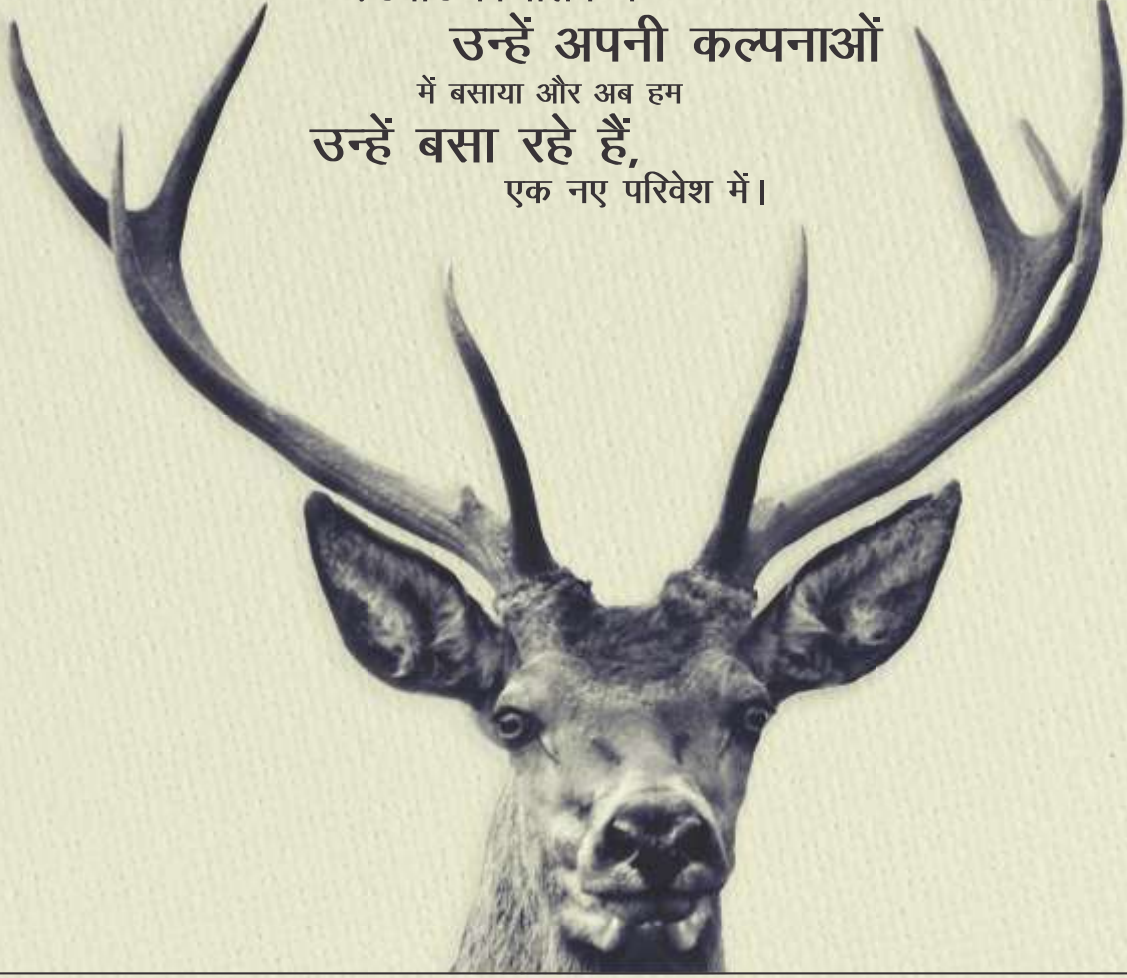
बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए प्लान की बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें.



ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी.

LIC/AR/17-18/19/HIN

रुडयार्ड किपलिंग ने
उन्हें अपनी कल्पनाओं
में बसाया और अब हम
उन्हें बसा रहे हैं,
एक नए परिवेश में।



“ओएनजीसी बारासिंघा (ईस्टर्न स्वैम्प डीअर) संरक्षण परियोजना”
एक दुर्लभ प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिये
ओएनजीसी की सीएसआर पहल।

असम में पाये जाने वाले बारासिंघा या ईस्टर्न स्वैम्प डीअर (*Rucervus duvaucelii ranjitsinhi*) आज विलुप्त होने की कगार पर है। प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने जिस से मंत्रमुग्ध हो कर उसकी सुन्दरता को अपनी दूसरी किताब 'द सेकंड जंगल बुक' में कैद किया हो, उस जीव के लिये यह काफी दुखद स्थिति है।

ओएनजीसी ने इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिये अपने कदम बढ़ाये, और वो भी बिल्कुल सही समय पर।

इसके पहले चरण के अन्तर्गत इनकी अनुमानित आबादी, अनुकूल पर्यावरण, पशु-चिकित्सा अंतःक्षेप एवं सामान्य अध्ययन और जागरूकता अभियान किया गया। इनके स्थानांतरण के लिये मानस राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया, जो इनके रहने के लिये बिल्कुल उपयुक्त स्थान था।

काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से 19 बारासिंघो को मानस में स्थानांतरित करना बहुत ही कठिन काम था। योजना के इस अत्यंत कठिन दूसरे चरण को दक्षिण अफ्रीका से बुलाये गये वन्यजीव विशेषज्ञों ने बहुत खास तरीके से अंजाम दिया। 19 बारासिंघो का स्थानांतरण खास तंबुओ में किया गया, जिनको अन्दर से उनके प्राकृतिक आवास जैसा ही बनाया गया था। कुछ ही महीनों में 6 नवजात बारासिंघो ने झुण्ड में जुड़कर, स्थानांतरण की खुशी को दुगना कर दिया।

इस योजना के विस्तार के तीसरे चरण के अन्तर्गत 20 अतिरिक्त बारासिंघो का स्थानांतरण किया जा रहा है।

यह परियोजना संतुलित पर्यावरण की ओर ओएनजीसी की एक शुरुआत है। लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करने के लिये प्रेरित, हमारा संगठन प्रकृति की असली सुंदरता को बनाये रखने के लिये प्रतिबद्ध है।



ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऊर्जा भवन, 5, नैलसन मंथेला मार्ग, वंसत कुंज, नई दिल्ली-110070
दूरभाष: 011-26752021, 26122148, फैक्स: 011-26129091 www.ongcindia.com f/ONGC Limited @ONGC_